श्रावण कृष्ण पक्ष-7, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 31 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
05 अगस्त 2026 बुधवार

आज का मौसम
30.4 अधिकतम
24.0 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

# दोपहर मेट्रो

Page-7

## न्यूज विंडो

### पेंचवैली एक्स. के एसी कोच में लगी आग, 72 को सुरक्षित निकाला

**भोपाल/इटारसी।** नैनपुर से इंदौर के बीच चलने वाली पेंचवैली एक्सप्रेस ट्रेन के बी2 एसी कोच में आज तड़के 4 बजे आग लग गई। कोच में अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन रोककर यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। कोच में करीब 72 यात्री सफर कर रहे थे। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। घटना इटारसी से पहले पोला पत्थर स्टेशन की बताई जा रही है। बी2 कोच फुल था और यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। धुआं फैलने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तुरंत चेन खींचकर ट्रेन रोकी गई।

### केमिकल लीक होने से हादसा, तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत

**यादगीर।** कर्नाटक की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहां फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से 3 मजदूरों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। मामला कदेचुर-बडियाल इंडस्ट्रियल एरिया का है। मृतक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी पहचान तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कटला गणेश और मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विक्रम सिंह गोंडा और संजय सिंह गोंडा के तौर पर हुई है। इस घटना के बाद फैक्ट्री में कामकाज रोक दिया गया। सैदापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

### ऑनलाइन संबोधन के माध्यम से आज 2 साल बाद दिखेंगी हसीना

**नई दिल्ली।** बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वे आज नई दिल्ली स्थित 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करेंगी। बांग्लादेश ने भारत से उनके भाषण पर रोक लगाने की मांग की है। भारत सरकार ने कहा है कि शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से हमारा कोई संबंध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा।

## आज का कार्टून

### क्या NCAHP Act-2021 की मूल भावना को प्रशासनिक व्याख्याओं ने बदल दिया?

# मोदी के हेल्थ विजन पर मध्यप्रदेश सरकार की अफसरशाही का ग्रहण !

**भोपाल**

भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में वर्षों तक डॉक्टरों को ही उपचार का केंद्र माना जाता रहा, जबकि किसी भी मरीज के स्वस्थ होने की वास्तविक यात्रा अस्पताल के बिस्तर से शुरू होकर पुनर्वास तक जाती है। यही वह चरण है, जहां फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और अन्य एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस आवश्यकता को समझा था। उनका मानना था कि आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था केवल डॉक्टरों के भरोसे नहीं चल सकती। मरीज को बेहतर, सस्ता और समय पर उपचार तभी मिलेगा, जब एलाइड हेल्थ प्रोफेशन को वैज्ञानिक पहचान, सम्मान और मजबूत नियामकीय व्यवस्था मिले।

दोपहर मेट्रो स्पेशल
राजेश सिरोठिया

इसी सोच का परिणाम था नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स (NCAHP) Act, 2021, जिसे संसद ने पारित किया। इस कानून का उद्देश्य केवल फर्जी पैरामेडिकल संस्थानों पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि एलाइड हेल्थ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और मरीजों को बेहतर पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना भी था।

**लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्यप्रदेश में इस कानून की मूल भावना को ही बदल दिया गया?**

दोपहर मेट्रो को उपलब्ध राजपत्र, विभागीय आदेश, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों तथा विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मार्च 2024 में मध्यप्रदेश सरकार ने पुराने पैरामेडिकल ढांचे को समाप्त कर स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल काउंसिल का गठन किया। इसकी अधिसूचना 14 मार्च 2024 को राजपत्र में प्रकाशित हुई। यह कदम NCAHP Act के अनुरूप था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2024 में इस परिषद को शिथिल कर पुरानी काउंसिल को फिर सक्रिय कर दिया गया।

**सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों किया गया?**

सरकारी रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि इसी अवधि में बड़ी संख्या में पैरामेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने की प्रक्रिया पूरी हुई। यदि उन संस्थानों को अनुमति ऐसे प्रावधानों के आधार पर दी गई जो NCAHP Act द्वारा निर्धारित मानकों से अलग थे, तो यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि उस सुधारवादी कानून की मूल भावना पर प्रश्नचिह्न है, जिसे संसद ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से बनाया था।

**यहीं से दूसरा और उतना ही गंभीर विवाद शुरू होता है...**

### आज सरकार के सामने हैं तीन सीधे प्रश्न...

**पहला-** जब NCAHP Act, 2021 लागू है, तो मध्यप्रदेश में उसके अनुरूप नियम और संस्थागत व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी क्यों नहीं है?

**दूसरा** - छह महीने पहले गठित एलाइड हेल्थ काउंसिल को शिथिल कर पुरानी पैरामेडिकल काउंसिल को पुनर्जीवित करने की प्रशासनिक आवश्यकता क्या थी?

**तीसरा-** Biomedical Waste Management Rules, 2016 के Rule 2 की विधिसम्मत व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जाता कि जिन फिजियोथेरेपी क्लीनिकों से बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पन्न नहीं होता, उन्हें प्राधिकरण लेने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है?

लोकतंत्र में कानून संसद बनाती है, नीतियां सरकार तय करती है और उनका ईमानदार तथा वैज्ञानिक क्रियान्वयन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यदि संसद की मंशा, वैज्ञानिक तथ्यों और जनहित के बीच प्रशासनिक व्याख्याएं दीवार बन जाएं, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या किसी पेशे का नहीं, बल्कि उस मरीज का होता है, जिसके लिए पूरा स्वास्थ्य तंत्र अस्तित्व में है।

प्रश्न केवल फिजियोथेरेपिस्टों का नहीं है। प्रश्न उस कानून की आत्मा का है, जिसे भारत की संसद ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों से इस क़ानून के इसके क्रियान्वयन को लेकर रिपोर्ट माँगी है जसवाल यही है कि क्या एमपी की सरकार इसे संजीदगी से लेगी ?

### नियमों का अध्ययन विधिक प्रश्न खड़ा करता है

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिजियोथेरेपी क्लीनिकों को Biomedical Waste Management Rules, 2016 के अंतर्गत प्राधिकरण लेने के दायरे में रखा है। स्वास्थ्य विभाग को दिए गए उत्तर में बोर्ड का तर्क है कि फिजियोथेरेपी क्लीनिक Clinical Establishment हैं, इसलिए उन पर भी यह नियम लागू होते हैं। लेकिन नियमों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न खड़ा करता है।

Biomedical Waste Management Rules, 2016 के Rule 2 (Applicability) के अनुसार यह नियम उन संस्थानों पर लागू होते हैं जो वास्तव में बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पन्न करते हैं अथवा उसका संग्रह, परिवहन, उपचार या निस्तारण करते हैं। यही इस पूरे विवाद का केंद्र है।

फिजियोथेरेपी की मानक उपचार प्रणाली व्यायाम, मैनुअल थेरेपी, पुनर्वास तकनीकों और इलेक्ट्रो-फिजिकल उपकरणों पर आधारित है। ऐसे उपचार में सामान्यतः वह जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता जिसके लिए Biomedical Waste Management Rules, 2016 के अंतर्गत प्राधिकरण आवश्यक माना गया है। ऐसी स्थिति में केवल Clinical Establishment की परिभाषा के आधार पर प्रत्येक फिजियोथेरेपी क्लीनिक को अनिवार्य रूप से Biomedical Waste Authorization लेने के लिए बाध्य करना नियमों की विधिक व्याख्या पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

यदि नियम की मूल शर्त 'Generate Biomedical Waste' है, तो यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जिन संस्थानों से ऐसा अपशिष्ट उत्पन्न ही नहीं होता, उन्हें किस विधिक आधार पर इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। इस निर्णय का सीधा प्रभाव केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। हजारों फिजियोथेरेपी क्लीनिकों पर प्रतिवर्ष अतिरिक्त आर्थिक और प्रशासनिक बोझ पड़ रहा है। फिजियोथेरेपी संगठनों द्वारा राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित प्राधिकरणों को अनेक प्रतिवेदन दिए गए, किंतु अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। विडंबना यह भी है कि विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों में भी इस मूल कानूनी प्रश्न का स्पष्ट समाधान सामने नहीं आया। इससे यह स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या संबंधित नियमों की व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों और विधिक प्रावधानों के अनुरूप की गई है। यह विवाद किसी एक पेशे का नहीं है। यह उस मरीज का प्रश्न है, जिसे स्ट्रोक, लकवा, रीढ़ की चोट, फ्रैक्चर, ऑपरेशन या लंबे समय तक आईसीयू में रहने के बाद पुनर्वास की आवश्यकता होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में फिजियोथेरेपी केवल दर्द कम करने की पद्धति नहीं, बल्कि उपचार प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। गंभीर रोगियों से लेकर आईसीयू तक में प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका आज विश्वभर में स्वीकार की जा चुकी है।

ऐसे में यदि एलाइड हेल्थ प्रोफेशन को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया कानून राज्य स्तर पर अपनी मूल भावना से भटकता दिखाई देता है, तो यह केवल प्रशासनिक बहस नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य का विषय बन जाता है।

**आरबीआई का ऐलान**

## लोन सस्ते नहीं, ईएमआई भी नहीं घटेगी, 5.25% रेपो रेट बरकरार

**नई दिल्ली, एजेंसी।** होम, कार और पर्सनल लोन लेने वालों को फिलहाल कम नहीं होंगी। उनकी ईएमआई भी अभी नहीं घटेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रखा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को फैसलों का ऐलान किया।उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उथल-पुथल और उससे बढ़े महंगाई के दबाव को देखते हुए फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

**नए लोन भी मौजूदा ब्याज दर पर मिलेंगे:** बैंक फिलहाल होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में तुरंत बदलाव नहीं करेंगे। नए लोन भी मौजूदा दरों पर ही मिलने की संभावना है।

**एफडी पर ब्याज में तुरंत बदलाव नहीं:** रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, अंतिम फैसला हर बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है।

**चार दिवसीय आयोजन**

## ब्रिक्स सम्मेलन आज से भोपाल में कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

**भोपाल, दोपहर मेट्रो।** प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 शुरू हो रहा है। 5 से 8 अगस्त तक चलने वाले इस चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की थीम पर किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मकसद ब्रिक्स देशों और आमंत्रित देशों के बीच कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम में भारत, ब्राजील, इथियोपिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात , दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, थाईलैंड और बेलारूस समेत 10 देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि और 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठकें 5 और 6 अगस्त को तय की गई हैं, जबकि संस्कृति मंत्रियों की बैठक 7 और 8 अगस्त को होगी।

**जम्मू-कश्मीर अलर्ट पर**

## 370 हटने के 7 साल पूरे, सुरक्षा बढ़ाई गई, अमरनाथ यात्रा रोकी

**श्रीनगर, एजेंसी।** जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज सात साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम समेत संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू है। हाईवे पर सुरक्षाबलों के काफिलों की आवाजाही रोक दी गई है।

वहीं, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा भी एक दिन के लिए रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ ने रामबन में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जबकि कुलगाम पुलिस ने एनएच-44 पर गाड़ियों और लोगों की आईडी की जांच तेज कर दी है। बिना परमिशन रैली और धरने पर रोक लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी समेत कई राजनीतिक दल आज 'ब्लैक डे' मना रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला और लोगों से विरोध दर्ज करने की अपील की।

**दतिया के नतीजे का मंथन और उसके सबब**

# हार के असली कारणों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

### खतरे की घंटी का अर्थ यह नहीं कि सब खत्म हो गया... सतर्क हो जाइए...

दतिया में भाजपा को यह भी ईमानदारी से देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने किस रूप में लिया। पार्टी नेतृत्व को पूरा अधिकार है कि वह किसी को भी प्रत्याशी बनाए या टिकट काटे, लेकिन राजनीतिक निर्णयों के परिणामों की समीक्षा भी उतनी ही निष्पक्षता से होनी चाहिए। यदि प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी व्यूह रचना तक फैसले ऊपर के स्तर पर हुए, तो हार की समीक्षा भी ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए, सिर्फ नीचे वालों को दंडित करके नहीं। रणनीतिक गलतियों का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ने का सिलसिला जारी रहा, तो भाजपा के लिए यह सोच आत्मघाती साबित हो सकती है। खतरे की घंटी का अर्थ यह नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया। उसका अर्थ होता है - सतर्क हो जाइए। समय रहते उसकी आवाज सुन ली जाए तो रास्ता सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि सत्ता और संगठन उस आवाज को भी अपनी सुविधा के मुताबिक समझने लगें, तो लोकतंत्र में जनता के पास अपना फैसला सुनाने का सबसे ताकतवर माध्यम मौजूद है - मतदान की मशीन का बटन। और जनता जब सबक सिखाने का फैसला कर लेती है, तो वह मौका शायद ही छोड़ती है।

हार-जीत के पार

अनिल शर्मा

गुजरात, बिहार और मध्यप्रदेश में हुए उपचुनावों के नतीजों को यदि महज तीन अलग-अलग सीटों का स्थानीय चुनावी परिणाम मानकर छोड़ दिया जाए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक संदेश को पढ़ने से चूक जाएगी, जो मतदाताओं ने इन चुनावों के जरिए देने की कोशिश की है। कहीं भाजपा हारी है, कहीं जीती है, लेकिन जीत वाली सीट पर भी उसका घटता जनाधार सवाल खड़े कर रहा है। तीनों नतीजों को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर पार्टी के लिए आत्ममंथन की मांग करती है।

बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से जुड़ी सीट पार्टी 18 हजार से अधिक मतों से हार गई। गुजरात की मांजलपुर सीट करीब 30 हजार मतों के अंतर से जरूर जीत ली, लेकिन चार वर्षों में जीत का अंतर करीब 70 हजार काम होना क्या सामान्य मान लिया जाए। इसी तरह एमपी की दतिया सीट पर भाजपा छह हजार मतों से हारी जो उसकी लगातार दूसरी हार है। तीनों सीटों की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मतदाताओं के रुख में आए बदलाव को समझने की कोशिश किए बिना केवल सुविधाजनक तर्क गढ़ना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। बिहार में रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता का वह बयान चर्चा में रहा, जिसमें भाजपा की चुनाव जिताने की ताकत को लेकर बेहद अहंकारी अंदाज में टिप्पणी की गई। राजनीति में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब यह अहंकार में बदलने लगे तो मतदाता अक्सर उसका जवाब मतदान केंद्र पर देता है।

दतिया सीट का मामला तो और भी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हार के बाद कहा कि ढाई वर्षों में भाजपा ने हार का अंतर करीब सत्रह सौ वोट कम किया है। यह तर्क भी दिया गया कि दतिया मूल रूप से भाजपा की सीट नहीं थी। यदि इन दोनों दलीलों को ही अंतिम सत्य मान लिया जाए, तो फिर एक सीधा सवाल है – हार के तुरंत बाद दतिया भाजपा की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हार अपेक्षित थी, सीट भाजपा की थी ही नहीं और हार का अंतर कम होना उपलब्धि है, तो जिला संगठन को सजा किस बात की मिली?

यदि जिला संगठन वास्तव में हार के लिए जिम्मेदार था, तो यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद जब जिले के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने इस्तीफे दिए थे, तब उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया गया? चुनाव अभियान के दौरान पुराने संगठन, विशेषकर नरोत्तम समर्थकों, को प्रभावी चुनावी भूमिका से दूर क्यों रखा गया? बूथ से लेकर पन्ना स्तर तक पुराने कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित कर नई व्यवस्था खड़ी की गई थी। यदि चुनावी रणनीति, प्रत्याशी चयन और अभियान संचालन नई व्यवस्था के हाथ में था, तो हार का ठीकरा पुराने संगठन पर कैसे फोड़ा जा सकता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दतिया का चुनाव केवल स्थानीय संगठन नहीं लड़ रहा था। दिल्ली से भोपाल तक भाजपा की पूरी ताकत वहां झोंकी गई। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से मंत्री, विधायक, सांसद और चुनाव लड़ाने में दक्ष पदाधिकारियों की फौज भेजी गई। बूथ प्रबंधन से लेकर मतदाता संपर्क तक हर स्तर पर संसाधन लगाए गए।

तो फिर जिम्मेदारी तय करते समय इस पूरी चुनावी कमान का मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इतनी बड़ी राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत लगाने के बाद हार का अंतर करीब सत्रह सौ वोट कम हो जाना ही प्रदेश भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाए? असल सवाल किसी एक नेता, जिला अध्यक्ष या कार्यकर्ता की जवाबदेही का नहीं है। सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का है जिसमें जीत का श्रेय ऊपर तक जाता है, लेकिन हार की जिम्मेदारी नीचे खड़े कार्यकर्ताओं पर डाल दी जाती है।

# जाम के दर्द से रोज घंटों कराह रहा लालघाटी-एयरपोर्ट रोड, जिम्मेदार हैं कि सुनते ही नहीं...

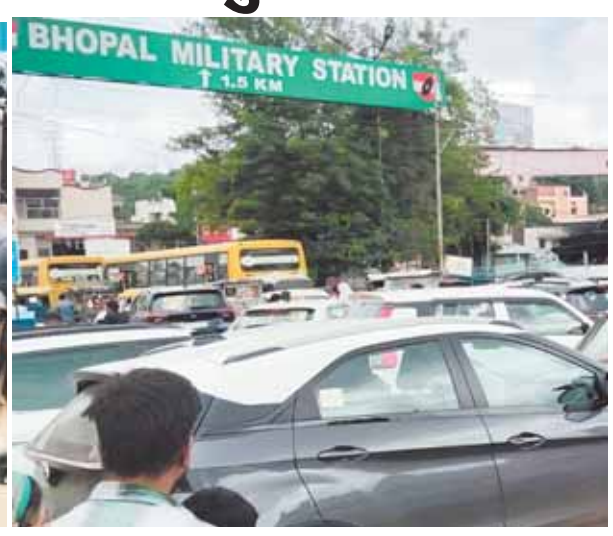


**भोपाल. दोपहर मेट्रो**

अव्यवस्थित यातायात, ऑटो और जहां-तहां सड़क किनारे गाड़ियों के खड़ी होने से राजधानी में लालघाटी एयरपोर्ट रोड पर लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन लोग ट्रैफिक जाम से परेशान हो रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार इस रोड पर सुबह लोगों का दफ्तर जाना और शाम में घर लौटना दूभर हो रहा है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों के साथ रहवासियों को रोजाना जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार सिस्टम नहीं सुधार पा रहे।

## कई जगह अतिक्रमण

कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। कई बार एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है रोज 20 से 40 मिनट तक जाम में फंसना आम बात हो गई है।

## लोग बोले-कार्रवाई से सुधरेंगे हालात

रहवासियों का कहना है कि एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित मौजूदगी, चौराहों पर बेहतर सिग्नल प्रबंधन और अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। शहर में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ रहा है और लालघाटी क्षेत्र भी भीड़भाड़ वाले प्रमुख इलाकों में शामिल है। हाल के समय में भी इस क्षेत्र में यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आती रही हैं।

## पीक आवर्स में तैनात हो अतिरिक्त पुलिस

स्थानीय नागरिकों ने कई बार जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस से इस जाम के जंजाल से निजात दिलाने की मांग की। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर लोगों ने प्रशासन, निगम और ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि यातायात व्यवस्था के लिए स्थायी कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने और पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल तैनात करने की मांग भी की गई है, ताकि जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।

### शिक्षा विभाग के संशोधित नियमों के उल्लंघन पर मान्यता होगी रद्द

# 25 हजार निजी स्कूलों ने छिपाई जानकारी सरकार ने बदले नियम...अब लुकाछिपी नहीं

**भोपाल. दोपहर मेट्रो**

भोपाल। प्रदेश के करीब 25 हजार निजी स्कूलों के नियमों के उल्लंघन करने और जानकारी शिक्षा विभाग से छिपाने के बाद सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। राज्य के निजी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता अब और पारदर्शी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था में बदलवा किया है। अब वे जानकारी नहीं छिपा सकेंगे। ऐसा किया या फिर गलत और फर्जी दस्तावेज के आधार पर मान्यता ली तो निजी स्कूलों पर दो लाख रुपए का तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के अनुसार सभी शिक्षकों को अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हालांकि संशोधित नियमों के तहत मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरे वर्ष किए जा सकेंगे। लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र के लिए केवल 30 सितंबर तक मिले आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। भौतिक सत्यापन, आपत्तियों और अपीलों सहित पूरी प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करना अनिवार्य रहेगा। नई व्यवस्था में स्कूलों को अपील का भी मौका दिया गया है। यदि संबंधित स्कूल या संस्था के आवेदन निरस्त हो जाते हैं तो संस्था पहले आयुक्त, लोक शिक्षण और उसके बाद राज्य मान्यता समिति के सामने तय समय सीमा में अपील कर सकेगी।

- फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत स्कूल फीस, यूनिफॉर्म श किताबों की लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं डाल रहे थे।
- अभिभावकों को विशेष दुकान से यूनिफॉर्म /किताबें खरीदने को बाध्य कर रहे थे।
- कई बिना लैब और पर्याप्त शिक्षकों के ही फर्जी दस्तावेज जमा कर स्कूल चला रहे थे।

## अब क्या-क्या जरूरी

हाईस्कूल स्तर पर कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कंपोजिट साइंस लैब अनिवार्य कर दी गई है। हायर सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग-अलग प्रयोगशालाएं होना जरूरी होगा।

- जिन स्कूलों में पर्याप्त भवन, सुरक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उन्हें दो पालियों में कक्षा लगाने की अनुमति भी मिल जाएगी।
- छात्र संख्या के आधार पर सुरक्षा जमा राशि भी तय कर दी है। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों को 25 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक की बैंक एफडी प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम से जमा करनी होगी।

## क्यों हुआ बदलाव

शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, 35 हजार मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में से 10,000 स्कूलों ने ही फीस और नियमों से जुड़ी अनिवार्य जानकारी सरकारी पोर्टल पर दर्ज की। 25 हजार स्कूलों ने नियम का सीधा उल्लंघन किया है।

**फीस घोटाला:** जबलपुर में तो सारी हदें पार हो गईं। जिला प्रशासन की जांच में 10 बड़े निजी स्कूलों को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। स्कूलों ने बिना अनुमति ही फीस बढ़ा दी। हालांकि प्रशासन ने स्कूलों को फीस लौटाने का भी आदेश दिया।

## यह भी बड़ा कारण

इंदौर और जबलपुर समेत कई शहरों में 11 निजी स्कूलों के खिलाफ किताबें और फीस घोटाले में एफआइआर दर्ज की गई। ये स्कूल जाली आइएसबीएन नंबर वाली किताबें चला रहे थे। वे अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से यही किताबें दोगुनी कीमत पर खरीदने को विवश कर रहे थे। इसके साथ ही 250 स्कूल ऐसे मिले, जिन्होंने पिछले सत्र में नियमों व इन्फ्रास्ट्रक्चर के मानकों को पूरा करने का भरोसा दिया। लेकिन यह कागजी ही रहा। नतीजा, सरकार ने 250 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद सरकार ने नियमों को और बेहतर करने की कवायद की।

### सुप्रीम कोर्ट में निगम रखेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट

# रिहायशी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी पर आज सुनवाई

**भोपाल. दोपहर मेट्रो**

भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर राज्य सरकार की रोक के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नगर निगम कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करेगा। दो दिन में 102 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट के सामने रखेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी पक्ष रखे जाएंगे। इसके बाद साफ हो जाएगा कि रिहायशी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी चलती रहेगी या सरकार के पाले में गेंद आएगी। बता दें, आवासीय प्रॉपर्टी पर कमर्शियल एक्टिविटी से अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कलां समेत अन्य क्षेत्रों के रहवासी परेशान हैं। रहवासी पूर्णेंदु शुक्ला एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

## यह गुंजाइश भी

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने जब कार्रवाई शुरू की तो व्यापारी विरोध में आ गए। 2005 में ही खत्म हो चुके मास्टर प्लान के बाद जैसे-तैसे भोपाल बढ़ने लगा। इसी कड़ी में आवासीय क्षेत्रों में दुकानें भी खुलीं। अब सरकार ने शीर्ष कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए नगरीय विकास के एसीएस की अगुवाई में टीम बनाई। यह टीम विकल्प तलाश कर रास्ता निकालेगी। जानकारों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इसे रखा जा सकता है। कोर्ट इस पर सहमत हुई तो व्यापारियों को राहत मिल जाएगी।

# साइबर ठगों ने हवलदार को बनाया निशाना, उड़ाए 1.96 लाख रुपए

**भोपाल. दोपहर मेट्रो।** राजधानी में साइबर अपराधियों ने इस बार एक पुलिसकर्मी को ही अपना शिकार बना लिया। कमलानगर थाने में पदस्थ हवलदार राजेंद्र बहादुर सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 1.96 लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने हवलदार के मोबाइल पर एक फर्जी लिंक भेजा था। लिंक पर क्लिक करते ही साइबर अपराधियों ने किसी तरह उनके बैंक खाते की जानकारी हासिल कर ली और अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए रकम निकाल ली। खाते से पैसे कटने के मैसेज मिले तो हवलदार को ठगी का पता चला।

# हुजूर: नांदनी में 1 रास्ते पर कब्जा, दूसरे पर सड़क नहीं, अंतिम यात्रा भी मुश्किल

**भोपाल. दोपहर मेट्रो**

राजधानी की सबसे बड़ी विधानसभा...हुजूर। यहां नांदनी गांव में लोगों की अंतिम यात्रा भी दुखदायी साबित हो रही है। मुक्तिधाम तक सड़क नहीं है। दूसरी ओर एक अन्य रास्ता है भी तो लोगों ने उस पर ही कब्जा जमा लिया है। नतीजा, जरा सी बारिश में मिट्टी भरी राह पर कीचड़ पसर जाता है। लोग परिजनों की शव यात्रा में घुटनों तक कीचड़भरी राह से गुजरने को विवश हैं। रविवार को ग्रामीणों ने इसी तरह महिला के शव को कंधों पर उठाकर दलदल जैसे रास्ते से

हुजूर में नांदनी गांव में मुक्तिधाम तक सड़क न होने से लोगों की अंतिम यात्रा भी परेशानियों से भरी है। बारिश में कीचड़भरी राह उनकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं।

अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया। दावों की एक बार फिर पोल खुल गई। ग्रामीणों ने मुक्तिधाम के रास्ते के लिए एसडीएम को पत्र भी लिखा है। सरपंच प्रतिनिधि राजेश वर्मा ने बताया कि मुक्तिधाम जाने का एक अन्य रास्ता भी है, लेकिन उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यही कारण है कि ग्रामीण कीचड़ भरे रास्ते से पहुंच रहे हैं।

# समय पर कैंसर की हो पहचान तो इलाज से बचेगी जान 18 साल से कर रहे लोगों को किया जा रहा जागरूक

### भोपाल कैंसर रिसर्च व वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन चतुर्वेदी को किया गया सम्मानित

**भोपाल. दोपहर मेट्रो**

**कैंसर** जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच एवं परामर्श के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करने के लिए 18 साल से सक्रिय भोपाल कैंसर रिसर्च व वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मनोज चतुर्वेदी को हाल ही में गरिमामय समारोह में सम्मानित किया गया।

कैंसर जागरूकता के क्षेत्र में संस्था लंबे समय से उल्लेखनीय योगदान

देती रही है। कई स्थानों पर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम, डिटेक्शन कैंप और काउंसलिंग भी करती रही है। इसका उद्देश्य कैंसर के शुरुआती लक्षणों की समय पर पहचान करने के साथ समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही वे लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 जी 2 में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन -पीडियाट्रिक कैंसर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं।

## जागरूकता की अलख

वे बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति भी जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस जानलेवा बीमारी की समय पर पहचान और जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। 18 वर्षों की यह यात्रा केवल एक संस्था या पद की उपलब्धि नहीं, बल्कि कैंसर के विरुद्ध जागरूकता की अलख जगाने और समाज के जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सहयोग पहुंचाने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

**मेट्रो एंकर** पीडब्ल्यूडी की सुस्ती से चार साल से डीपीआर नहीं बनी, निर्माण कार्य भी अधर में ही लटका

# भोपाल में देश के पहले सरकारी हम्माम सेंटर पर लगा ब्रेक

**भोपाल. दोपहर मेट्रो**

राजधानी के कलियासोत स्थित हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रस्तावित देश का पहला सरकारी हम्माम सेंटर अब भी अधर में लटका हुआ है। करीब चार साल पहले घोषित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सुस्ती के कारण शुरू नहीं हो सका है।

कॉलेज परिसर में 3,000 वर्गफीट भूमि पहले ही आरक्षित की जा चुकी है, लेकिन अब तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं होने से टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। शुरुआती दौर में इस परियोजना की लागत तीन करोड़ रुपये तय की गई थी, लेकिन लगातार देरी के कारण इसके बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हम्माम सेंटर में यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत मरीजों को बॉडी डिटॉक्स और कई गंभीर बीमारियों का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

इसकी पूरी थेरेपी 90 मिनट की होगी, जिसमें अलग-अलग तापमान वाले तीन विशेष कमरे बनाए जाएंगे। अंतिम थेरेपी कक्ष को गुंबदाकार डिजाइन में तैयार किया जाएगा, जिसमें तांबे की पाइपलाइन, थर्मा-रेजिस्टेंट टाइल्स और एलपीजी आधारित हीटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। यहां एक समय में तीन मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. महबूबा बेगम के अनुसार, पीडब्ल्यूडी को डीपीआर तैयार करने के लिए पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट मिलते ही निर्माण और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

## 90 मिनट में पूरी होगी तीन चरणों की थेरेपी

हम्माम सेंटर में मरीजों के उपचार के लिए तीन अलग-अलग तापमान वाले कमरे बनाए जाएंगे। पहले 'कंफर्ट जोन' में मरीज को 10 से 15 मिनट तक 22 से 24 डिग्री तापमान में रखा जाएगा, ताकि शरीर सामान्य अवस्था में आ सके। इसके बाद मरीज को 'गर्म जोन' में भेजा जाएगा, जहां तापमान 36.5 से 38 डिग्री रहेगा और पसीना निकालने की प्रक्रिया होगी। तीसरा और सबसे बड़ा थेरेपी रूम 42 से 47 डिग्री तापमान वाला होगा, जहां गर्म पानी और भाप की मदद से उपचार किया जाएगा। यहां एक साथ तीन मरीजों का इलाज तीन सहायकों की निगरानी में किया जा सकेगा।

## गुंबदनुमा डिजाइन और आधुनिक तकनीक होगी खासियत

प्रस्तावित हम्माम सेंटर का मुख्य थेरेपी कक्ष गुंबदनुमा बनाया जाएगा। कमरे में छोटे-छोटे कांच के झरोखे और विशेष कलाकृतियां होंगी, ताकि मरीजों को मानसिक शांति मिल सके। भाप के बेहतर प्रवाह के लिए दीवारों में तांबे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जबकि फर्श पर थर्मा-रेजिस्टेंट टाइल्स और विशेष ईंटों का इस्तेमाल होगा। पानी गर्म करने के लिए एलपीजी गैस आधारित प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे बिजली के करंट का खतरा नहीं रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सेंटर यूनानी चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार के क्षेत्र में देश के लिए एक नई पहल साबित होगा।

# नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाह समाज से खेद व्यक्त किया

**भोपाल।** विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी एक टिप्पणी के लिए कुशवाह समाज से खेद व्यक्त किया है। श्री तोमर ने कहा कि वे विगत दिनों कमलेश कुशवाह के घर गए थे। यह पारिवारिक कार्यक्रम था और उसी माहौल में चर्चा हो रही थी। कुशवाह समाज का वे जीवनभर सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वे समाज का अपमान करने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। उनकी टिप्पणी से अगर किसी को ठेस लगी है तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं और खेद व्यक्त करते हैं।

### बेतवा के खतरनाक पिलरों पर छलांग लगाने की मजबूरी खत्म, सात गांवों के बच्चों को मिलेगा फायदा

# वीडियो ने बदली बच्चों की किस्मत, तीन दिन में सरकार ने खोला नया स्कूल

**विदिशा, दोपहर मेट्रो**

विदिशा। बेतवा नदी के स्टॉप डैम के पिलरों पर छलांग लगाकर स्कूल जाने को मजबूर ककरुआ सहित तीन गांव के बच्चों को अब बंधेरा गांव में ही नया हाई स्कूल मिल गया है। राज्य सरकार ने इस गांव के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा देते हुए आज बुधवार से कक्षा 9 वीं और दसवीं की कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी कर दिए है। इससे अब बच्चों को जान जोखिम में डालकर उफनती बेतवा नदी के चेक डैम पर बने दो-दो फीट चौड़े पिलरों पर छलांग लगाकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।

बेतवा नदी के किनारे बसे ककरुआ गांव में केवल आठवीं तक का स्कूल है। इसके बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को सड़क मार्ग से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पलोह स्कूल जाना पड़ता था। लंबी दूरी से बचने के लिए बच्चे बेतवा नदी के स्टॉप डैम को पार करते थे, जहां कंक्रीट के खुले पिलरों पर संतुलन बनाते हुए एक से दूसरे पिलर पर छलांग लगानी पड़ती थी।

इस रास्ते से दूरी घटकर करीब डेढ़ किलोमीटर रह जाती थी, लेकिन हर दिन मौत का खतरा भी साथ चलता था। ककरुआ के दो, इमलिया के दो और बंधेरा के पांच , इस तरह कुल नौ बच्चे स्टॉप डैम पार कर नदी के दूसरे तट पर बसे पलोह गांव के स्कूल पहुंचते थे।

मानसून के दौरान जब डैम के ऊपर पानी बहता है और पिलर फिसलन भरे हो जाते हैं, तब यह सफर और अधिक खतरनाक हो जाता था। अभिभावकों का कहना था कि रोज बच्चों को छोड़ने और लेने जाना संभव नहीं होता, इसलिए मजबूरी में उन्हें इसी रास्ते से भेजना पड़ता था।

#### आज से ही पढ़ाई शुरू

लोक शिक्षण संचालनालय से ग्राम बंधेरा में स्थित मिडिल स्कूल का हाई स्कूल के लिए उन्नयन कर दिया है। यह आदेश प्राप्त होते ही दो शिक्षकों को भी यहां नियुक्त कर दिया गया है। आज से बंधेरा में ही कक्षा 9 वीं और 10 वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

– एनके अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा।

#### वीडियो के बाद जागी सरकार

मुंडरा हरिसिंह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ककरुआ के ग्रामीण बताते है कि गांव के बच्चे पिछले साल भी इसी तरह स्टॉप डैम पार कर स्कूल जाते थे। कुछ साल पहले ग्राम पंचायत ने इस क्षेत्र में हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी भेजा था लेकिन बच्चों की संख्या कम होने से इस क्षेत्र में हाई स्कूल नहीं खुला। तीन दिन पहले जब बच्चों का स्टॉप डैम पार करने वाला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हुआ तो यह मुद्दा देश भर में छा गया। इसके बाद सरकार के अधिकारी गांव पहुंचने लगे और तीन दिन के अंदर हाई स्कूल खोलने की घोषणा हो गई ।इस पंचायत के रोजगार सहायक विष्णु शर्मा कहते है कि बंधेरा में हाई स्कूल खुलने से सात गांवों को फायदा होगा।

## 15 अगस्त तक पूरा हो छात्रावास और मैस का काम : कृष्णा गौर

**भोपाल।** पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा घुमंतु एवं अर्धघुमंतु कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यमंत्री गौर ने विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं छात्रावासों में सुविधाओं के विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने छात्रावासों में मेस संचालन की तैयारियों में हो रहे विलंब पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि 107 छात्रावासों में चल रहे सभी निर्माण कार्य 15 अगस्त तक हर हाल में पूरे किए जाएं, जिससे विद्यार्थियों को समय पर पौष्टिक भोजन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए । आयुक्त सत्येंद्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश भर के 107 बालक एवं कन्या छात्रावासों में मेस संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

### भोपाल में उच्च शिक्षा का नया विजन, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले

# नई शिक्षा नीति युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कर रही है तैयार

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप उच्च शिक्षा को तैयार करने पर व्यापक चर्चा हुई। ÷उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम ¬ दृष्टि, दिशा एवं क्रियान्वयन÷ विषय पर आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में देशभर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ, विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

#### मुख्यमंत्री बोले- नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं को नैतिक मूल्यों, आधुनिक तकनीक और कौशल से जोड़ने का सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए विद्यार्थी समय की मांग के अनुरूप शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने के साथ देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों को जमीन पर उतारने के लिए विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है और इसके लिए विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

#### रोजगारोन्मुख और तकनीक आधारित पाठ्यक्रमों पर जोर

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक, बहुविषयक, रोजगारोन्मुख और तकनीक-सक्षम बनाना है। इसके तहत बदलती वैश्विक जरूरतों, उद्योगों की मांग और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया। विशेषज्ञों ने माना कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उसे रोजगार, नवाचार और कौशल विकास से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

#### भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा पाठ्यक्रम में स्थान: परमार

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ उनके कौशल विकास और बेहतर प्लेसमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

#### कृषि, एआई और तकनीकी शिक्षा पर विशेष फोकस

उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में कृषि संकाय के पाठ्यक्रमों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और नई तकनीकों से जुड़े विषयों को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में हजारों सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है तथा फैकल्टी डेवलपमेंट और क्षमता निर्माण के लिए लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

#### विशेषज्ञों ने शिक्षा और भारतीयता पर रखा जोर

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो विचार, व्यवहार और बौद्धिक दृष्टि से भारतीय मूल्यों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय ज्ञान का संतुलित समावेश ही विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक सोच को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर मनु संथानम ने मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू किए। इन समझौतों के माध्यम से डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाएगा।

### दतिया की पराजय पर मंथन तेज, मंत्री विजयवर्गीय बोले-

# हार-हार होती है, परिणाम पर गंभीरता से विचार जरूरी

**इंदौर, दोपहर मेट्रो**

दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद पार्टी ने आत्ममंथन की तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन हार को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों की संगठनात्मक समीक्षा होगी और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किन कारणों से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।

विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। उन्होंने दो टूक कहा कि हार, हार होती है और जीत, जीत होती है। इसलिए इस परिणाम पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी समीक्षा की बात कह चुके हैं। संगठन हर स्तर पर चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करेगा। जहां भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

#### पीके की जीत को बताया व्यक्ति आधारित प्रभाव

बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गृहक्षेत्र की सीट पर जनसुराज समर्थित उम्मीदवार की जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि वह पूरी तरह व्यक्ति-आधारित चुनाव था। उनके अनुसार, प्रशांत किशोर भले स्वयं चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन उनके प्रभाव का असर उस सीट पर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं वहां प्रचार करने गए थे और भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल भी था, लेकिन कुछ सीटों पर स्थानीय और व्यक्तिगत समीकरण चुनाव परिणाम बदल देते हैं।

#### रेवती रेंज में फिर हरियाली का नया अभियान

राजनीतिक बयानबाजी के साथ विजयवर्गीय ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को रेवती रेंज में एक दिन में एक लाख पौधे लगाने का अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी.एल. संतोष भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पहले इसी रेवती रेंज में 12 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार भी बड़ी संख्या में लोग अभियान से जुड़ेंगे और हरियाली बढ़ाने का संदेश देंगे।

### एमपी बीटेक एडमिशन में 39 हजार से ज्यादा सीटें खाली

# दो चरणों की काउंसलिंग पूरी, अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग से उम्मीद

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में बीटेक प्रवेश प्रक्रिया के तहत दो चरणों की आनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग (सीसीसी) पूरी हो चुकी है। इसके बाद विद्यार्थियों को आंतरिक ब्रांच परिवर्तन (इंटरनल ब्रांच चेंज) का अवसर दिया गया। जिन संस्थानों में संबंधित शाखाओं में सीटें खाली थीं, वहां आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को ब्रांच परिवर्तन का आवंटन जारी कर दिया गया।

**अब प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण कालेज लेवल काउंसलिंग-** अब प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण कालेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) होगा, जो सात अगस्त से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग (डीटीई) के 31 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 135 इंजीनियरिंग संस्थानों में बीटेक की कुल 75,249 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें अब तक 52,248 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया, जबकि 56,414 अभ्यर्थियों ने चाइस फिलिंग की।

#### काउंसलिंग के बाद 35,660 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश

दो चरणों की काउंसलिंग के बाद कुल 35,660 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इसके बावजूद अभी 39,589 सीटें रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए कालेजों की उम्मीद अब सीएलसी पर टिकी है। ब्रांचवार प्रवेश में इस बार भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) सबसे अधिक पसंद की जाने वाली शाखा रही। करीब 21 हजार सीटों में से लगभग सात हजार विद्यार्थियों ने सीएसई में प्रवेश लिया। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का स्थान रहा, जहां 7,201 सीटों में से 1,042 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया।

## MP-UDC में गुजरात की कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा

# 6.57 करोड़ की जाली बैंक गारंटी पर दिया ठेका, भोपाल में एफआईआर दर्ज

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपी-यूडीसी) ने जाली बैंक गारंटी के आधार पर गुजरात की एक कंपनी को करोड़ों रुपयों का ठेका दे दिया। काम पूरा होने के बाद जब बैंक से पत्राचार हुआ तो फर्जीवाड़े का पता चला। अब एमपी-यूडीसी के वित्त नियंत्रक सौरभ तिवारी ने भोपाल के एमपी नगर थाने में सूरत की इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड- (ज्वाइंट वेंचर विद साउथ गुजरात कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, एमपी-यूडीसी मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नल-जल और सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराती है। 2024 में इस सरकारी कंपनी ने टेंडर के जरिए एडीबी फेज-1, एडीबी फेज-2 और विशेष निधि के अंतर्गत मंडलेश्वर परियोजना का काम आवंटित किया था। यह काम इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कंपनी प्रा.लि. को मिला।

अनुबंध के तहत इस कंपनी ने निष्पादन और सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में करीब 6.57 करोड़ रुपये की आठ बैंक गारंटी जमा कराई थीं। यह बैंक गारंटी बैंक आफ इंडिया की साकीनाका (मुंबई) और आइसीआइसीआइ बैंक, तीनहाट नाका (ठाणे) के नाम से बनाई गई थी। एमपी-यूडीसी के अधिकारियों ने बैंक गारंटी को पुष्ट करने के लिए बैंकों के अधिकृत पते पर जाने के स्थान पर ई-मेल भेजा, जो बैंक गारंटी वाले दस्तावेज पर दर्ज थीं। जवाब में बैंक गारंटी सही होने की पुष्टि भी मिल गई। इस पुष्टि के आधार पर अनुबंध प्रभावी कर दिए गए और संबंधित फर्म ने परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया। बाद में बैंक गारंटी के मूल दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक से संबंधित बैंक शाखाओं को भेजकर भौतिक सत्यापन कराया गया।

#### संचालकों के नंबर भी बंद

पुलिस ने जांच के दौरान कंपनी के संचालक से पूछताछ के लिए उपलब्ध मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन दोनों नंबर बंद मिले। इसके कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। पुलिस अब कंपनी के संचालकों और इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। बता दें कि बैंक गारंटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ठेकेदार शर्तों का पालन न करे तो उसकी राशि जब्त की जा सके।

# पशुपालन विभाग के तबादलों का विवाद सीएम दफ्तर पहुंचा

**भोपाल।** तबादला सीजन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में किए गए प्रशासनिक तबादलों के विरोध में प्रदेशभर के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर तबादला आदेश निरस्त करने की मांग की। प्रभावित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा पशुपालन विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने सार्थक एप के आधार पर किए गए तबादलों को भी औचित्यहीन बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तथा पशुपालन विभाग के सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पशुपालन विभाग द्वारा 15 जून, 16 जून और 18 जून 2026 को जारी स्थानांतरण आदेशों में राज्य की स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है कि कई तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के बजाय मनमाने ढंग से किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

#### नोडल अधिकारी पर भी उठाए सवाल

ज्ञापन में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बिना वास्तविक परिस्थितियों की जांच किए केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर अधिकारियों का 700 से 1000 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया।

**मेट्रो एंकर** | 4,013 नागरिकों की मानव श्रृंखला को लंदन की विश्व रिकॉर्ड संस्था ने दी मान्यता

# नशामुक्ति की मुहिम को विश्व पहचान, मप्र पुलिस ने रचा कीर्तिमान

**भोपाल, दोपहर मेट्रो**

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 ने सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शासकीय रेलवे पुलिस, रेल इकाई इंदौर द्वारा 16 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ 4,013 नागरिकों की मानव श्रृंखला बनाकर नशामुक्ति का संदेश देने के प्रयास को लंदन की विश्व रिकॉर्ड संस्था ने सम्मानित किया है। यह सम्मान नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे जनभागीदारी आधारित प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। इस उपलब्धि ने प्रदेश पुलिस के सामाजिक अभियानों को नई पहचान दिलाई है।

21 जुलाई 2026 को रेल इकाई इंदौर के अंतर्गत आने वाले 16 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नागदा, नीमच, मेघनगर, शामगढ़, ब्यावरा, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, शाजापुर, मक्सी, देवास, डॉ. अंबेडकर नगर और चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन शामिल रहे।

इन सभी स्थानों पर कुल 4,013 नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशे से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इस अभियान में स्कूली छात्र-छात्राओं, रेल यात्रियों, कुलियों, रेलवे वेंडरों, सफाई कर्मियों, ऑटो रिक्शा चालकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। प्रतिभागियों ने ÷नशे से दूरी है जरूरी÷, ÷नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो÷ और ÷स्वस्थ युवा, सशक्त भारत÷ जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। मानव श्रृंखला के माध्यम से समाज को संदेश दिया गया कि नशे से मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

#### पहले भी मिल चुकी हैं कई अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां

मध्यप्रदेश पुलिस के इस अभियान को इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल चुकी है। इंदौर द्वारा आयोजित दो अलग-अलग जनजागरूकता कार्यक्रमों सहित बड़वानी, बुरहानपुर और बालाघाट में हुए विशेष अभियानों को भी लंदन की विश्व रिकॉर्ड संस्था द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। जीआरपी इंदौर की यह उपलब्धि नशामुक्ति अभियान की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण अध्याय है।

## लीक होता भरोसा

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं की आंखों में पलते सपनों से बनता है। वे सपने, जो वर्षों की मेहनत, अनगिनत रातों की जाग और परिवार की उम्मीदों से आकार लेते हैं। लेकिन जब परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र से पहले बाजार तक पहुंच जाए, तब केवल एक पेपर लीक नहीं होता, बल्कि व्यवस्था पर टिका विश्वास भी चुपचाप रिसने लगता है। यही कारण है कि एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक का संसद से पारित होना महज एक विधायी घटना नहीं, बल्कि उस भरोसे को पुनः स्थापित करने का प्रयास है, जिसे पिछले कुछ वर्षों में बार-बार ठेस पहुंची है। विडंबना यह है कि जिस विषय पर देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाएं टिकी थीं, वही विषय संसद में राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों के शोर में उलझता दिखाई दिया। लंबी बहस हुई, अनेक सांसदों ने अपने विचार रखे, संशोधन सुझाए गए, लेकिन अंततः बहस का बड़ा हिस्सा कानून की भावना से अधिक राजनीतिक संघर्ष का मंच बन गया। लोकतंत्र में मतभेद आवश्यक हैं, किंतु जब संवाद का स्तर तथ्यों से अधिक उत्तेजना और कटुता पर टिकने लगे, तब संसद की गरिमा भी प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। छात्र आंदोलनों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए। किसी ने कठोर कार्रवाई के आरोप लगाए तो किसी ने उन्हें पूरी तरह खारिज किया। अलग-अलग संस्थानों और अभिलेखों में दिखाई देने वाले विरोधाभास यह भी संकेत देते हैं कि केवल घटनाओं की जांच ही नहीं, बल्कि सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय और पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सवालों से नहीं डरता, बल्कि उनका तथ्यपरक उत्तर देता है। लेकिन इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अधूरा है*क्या केवल कठोर कानून बना देने से शिक्षा व्यवस्था की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर स्पष्ट है-नहीं। पेपर लीक एक लक्षण है, बीमारी उससे कहीं गहरी है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच असमान हो, सरकारी संस्थानों पर भरोसा कमजोर पड़ रहा हो, प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार विवादों में घिरती हों और लाखों युवाओं का करियर वर्षों तक अधर में लटका रहे, तब समस्या केवल अपराधियों की नहीं, पूरी व्यवस्था की बन जाती है। भारत का युवा केवल निष्पक्ष परीक्षा नहीं चाहता; वह निष्पक्ष अवसर भी चाहता है।

# देश में आरक्षण की दशा और दिशा आज भी है तीखी बहस का मुद्दा

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी
स्तंभकार

देश में आरक्षण का प्रश्न केवल राजनीति का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा विषय है। आजादी के लगभग 80 वर्ष बाद भी आरक्षण पर बहस उतनी ही तीखी है जितनी संविधान लागू होने के समय थी। एक पक्ष इसे ऐतिहासिक अन्याय के प्रतिकार का आवश्यक साधन मानता है, जबकि दूसरा पक्ष यह मानता है कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉ. भीमराव राव आंबेडकर ने आरक्षण को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करने का एक संवैधानिक साधन माना था। संविधान सभा की चर्चाओं में उन्होंने यह कहा था कि उद्देश्य समान अवसर उपलब्ध कराना है, ना कि समाज को स्थायी रूप से विभाजित करना।

संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक आरक्षण प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए रखा गया था, जिसे बाद में संसद ने समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया। वहीं, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान ने कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की। डॉ. आंबेडकर जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को भारतीय समाज की गंभीर समस्या मानते थे। 1932 के पूना समझौते के बाद पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था बनी। यह समझौता डॉ. आंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, इसलिए यह कहना कि वे केवल किसी एक पक्ष के दबाव में आरक्षण के पक्षधर हुए, इतिहास का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारों, विशेषकर कांग्रेस के लंबे शासनकाल में, आरक्षण व्यवस्था को बनाये रखा गया और समय-समय पर उसका विस्तार भी हुआ। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय जनता दल सरकार ने लिया, जबकि बाद की विभिन्न सरकारों ने भी आरक्षण संबंधी प्रावधानों को जारी रखा। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस ) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी लागू किया गया, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का एक नया उदाहरण है, जो केन्द्र सरकार की एक उपलब्धि है।

आरक्षण व्यवस्था की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसका लाभ कई बार एक ही परिवार या अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाता है। अनेक विशेषज्ञों का मत है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर भी ऐसे परिवार हैं जिन्हें बार-बार आरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि उसी समुदाय के अत्यंत गरीब और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी अवसरों से वंचित हैं। यही कारण है कि आरक्षण की समीक्षा, लाभार्थियों की पहचान और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। दूसरी ओर, आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक भेदभाव केवल आर्थिक स्थिति से समाप्त नहीं हो जाता। उनका कहना है कि आज भी अनेक क्षेत्रों में जाति आधारित भेदभाव मौजूद है, इसलिए केवल आर्थिक आधार पर्याप्त नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय ने भी कई मामलों में माना है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन आरक्षण का महत्वपूर्ण आधार है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि लंबे समय तक आरक्षण जारी रहने से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं में अवसरों की कमी की भावना उत्पन्न हुई है, इसी बहस के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण को लागू किया गया, जिससे आर्थिक आधार को भी नीति का हिस्सा बनाया गया। आज सत्ता और विपक्ष की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं करतीं।

इसका एक कारण यह है कि आरक्षण करोड़ों लोगों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है। दूसरा कारण यह है कि भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक वर्ग महत्वपूर्ण मतदाता हैं और कोई भी दल इस विषय पर अत्यधिक जोखिम नहीं लेना चाहता। साथ ही, कई दलों का मानना है कि जब तक सामाजिक असमानताएं पूरी तरह समाप्त नहीं होतीं, तब तक आरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। भविष्य की दृष्टि से अनेक नीति विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर निष्पक्ष समीक्षा हो, वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचे, गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक निवेश हो तथा जिन वर्गों में अपेक्षाकृत संपन्न तबका लगातार लाभ ले रहा है, वहां सुधार के विकल्पों पर विचार किया जाए। इससे सामाजिक न्याय और समान अवसर दोनों उद्देश्यों के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।

अंततः यह प्रश्न केवल 'जातिगत आरक्षण बनाम आर्थिक आरक्षण' का नहीं है। भारत जैसे विविध समाज में नीति-निर्माण का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक भेदभाव से प्रभावित लोगों को न्याय भी मिले और आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर भी। आरक्षण पर बहस तथ्यों, संविधान और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल भावनाओं या राजनीतिक नारों के आधार पर।

**-यह लेखक के अपने विचार हैं।**

# पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बदलाव की तस्वीर और निर्णायक लड़ाई

प्रमोद भार्गव
स्तंभकार

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लगातार हालात हिंसक एवं तनावपूर्ण हुए हैं। रावलकोट और मीरपुर में हिंसा के चलते संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 37 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने पीओजेके के इन हालातों पर गंभीर चिंता जताई है।

गौरतलब है कि जेएएसी पिछले करीब दो माह से पीओजेके की तथाकथित विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर आंदोलन चला रही है। संगठन का आरोप है कि ये 'शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्र' उन मतदाताओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, जो पीओजेके के मूल निवासी नहीं है। इनमें से ज्यादातर की वैधानिक पुष्टि भी नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार इन सीटों के जरिए अपनी पसंद की सरकार चुनवा कर मर्जी का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसी मनमानी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा बिजली, सस्ता आटा और अन्य खाद्य सामग्री की कमी भी आक्रोश का कारण बनी हुई है। भारत ने इन इन चुनावों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश कहा है। जबकि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है।

पीओजेके में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक तीन चरणों में चुनाव होने हैं। चुनावों में कुल 45 सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। किंतु गुलाम जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटें मंजूर नहीं हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग जबरदस्त विरोध में उतर आए हैं। इस विरोध के चलते पहले 46 प्रदर्शनकारी और अब मतदान के दौरान 37 लोग मारे जा चुके हैं, सैंकड़ों लोग घायल हैं। पाक आर्मी और पुलिस के इस दमन एवं नरसंहार से आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़क गया है। इस नाराजगी को दबाने के लिए पुंछ, मीरपुर एवं मुजफ्फराबाद में बड़ी संख्या में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए हैं। दरअसल लोगों का गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि ये चुनाव अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं मानवाधिकार आयोग को यह दिखाने के लिए कराए जा रहे हैं कि पाकिस्तान लोकतंत्र का पैरोकार है। लेकिन यह पूरा नाटक फरेब की नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। भारत भी इस चुनाव के विरोध में है।

इस विरोध का प्रमुख कारण पीओजेके में विधानसभा की 45 निर्वाचित सीटों में से 12 सीटों का शरणार्थियों के लिए आरक्षित करना है। जेएएसी का आरोप है कि इन सीटों के कारण स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। संगठन लंबे समय से इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहा है। चुनाव के ठीक पहले यह मुद्दा राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बन गया है। इस मुद्दे के साथ-साथ आमजन बढ़ती महंगाई, गेहूं और आटे की उपलब्धता में कमी, बिजली दरों में वृद्धि, बेरोजगारी तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारों की मांग को भी आगे बढ़ा रहा है।

दरअसल शरणार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने का मतलब स्थानीय लोगों को जनप्रतिनिधित्व से बहिष्कृत करने का संवैधानिक उपाय पाकिस्तान ने मान लिया है। अतएव ये चुनावी फरेब पीओजेके पर अवैध कब्जे को वैध ठहराने का उपाय भर है। पाकिस्तान इस चुनाव के जरिए यह जताने का उपक्रम कर लेता है कि वह लोकतंत्र का पक्षधर होने के साथ भू-राजनीतिक शक्ति भी है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को इस चुनावी हथकंडे को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के परिदृश्य में इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेश करने के साथ हस्तक्षेप की मांग करने की जरूरत है।

हालांकि पीओके में हुई हिंसा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाक पर करारा हमला बोला है। कहा है कि पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए। पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं को छुपाने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने के लिए झूठी खबरों और फर्जी वीडियो का सहारा ले रहा है। जबकि पीओजेके में आर्मी और पुलिस ने बर्बर कार्रवाही की है। हम उम्मीद करते है कि विश्व समुदाय पाक के इन कृत्यों के लिए उसे जवाबदेह ठहराएगा। वर्तमान नरसंहार को लेकर ब्रिटेन के 50 सांसदों ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदायों के समक्ष चिंता जताई है। भारत को पीओजेके में उभरे इस आंतरिक संकट और नरसंहार से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि धूर्त पाकिस्तान इस ओट में अपनी पुरानी और नापाक चालें चलते हुए प्रशिक्षित आतंकियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की चाल चल सकता है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस अराजकता और खून-खराबे की आड़ में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य नगरों में हिंसा व अशांति फैलाने की दृष्टि से आत्मघाती हमले करा सकती है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं।

इधर, पीओजेके में आमजनों पर सुरक्षा बलों की बर्बरता को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उचित ठहराया है। उन्होंने अधिकारों और पहचान दिए जाने की मांग कर रहे कश्मीरियों को भारत जैसा दुश्मन करार दिया है। आसिफ के इस बयान को इस तथ्य की स्वीकार्यता माना जा रहा है कि गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय जम्मू-कश्मीर की भूमि का हिस्सा हैं। हकीकत भी यही है। पीओजेके की परिधि में आने वाले गिलगित-बाल्टिस्तान वास्तव में भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्सा हैं। बावजूद पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। लेकिन यहां के नागरिकों ने इस बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां तभी से राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं और पाक सरकार इन लोगों पर दमन और अत्याचार का सिलसिला जारी रखे हुए है।

अतएव इन क्षेत्रों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होना चाहिए। क्योंकि भारत के पास अपनी स्थिति को मजबूती से रखने के लिए राजनीतिक कानूनी और संवैधानिक आधार मौजूद हैं। पाकिस्तान यहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्यात्मक घनत्व बदलने के प्रयास में भी लगा है। इन कारणों से यहां के मूल बलूचों की पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त नाराजी है और वे निर्णायक लड़ाई लड़के भारत में विलय होने की कोशिश में हैं।

**-यह लेखक के अपने विचार हैं।**

**हेल्थ अपडेट**

# स्पाइन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं कुछ ख़ास एक्सरसाइज

**भागदौड़** भरी जिंदगी में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, गलत पॉश्चर, शारीरिक गतिविधि की कमी और बढ़ता मोटापा रीढ़ और उससे जुड़ी मांसपेशियों को कमजोर बना रहे हैं। कमजोर स्पाइनल मसल्स न केवल कमर दर्द और गर्दन के दर्द का कारण बन सकती हैं, बल्कि संतुलन, लचीलापन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी असर डालती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ आसान फ्लोर एक्सरसाइज नियमित रूप से करने से रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है। यदि किसी को हाल ही में स्पाइनल फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क, गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस, लगातार नस दबने का दर्द या सर्जरी हुई है, तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के व्यायाम शुरू नहीं करना चाहिए।

**बर्ड डॉग:** एनसीबीआई के मुताबिक यह एक्सरसाइज रीढ़ को स्थिर रखने वाली मांसपेशियों, ग्लूट्स और कोर को मजबूत करती है तथा संतुलन सुधारती है। इसे करने के लिए आप हाथों और घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए बैठें। दायां हाथ और बायां पैर एक साथ सीधा करें। इस पोजीशन में 5 सेकंड रूकें। फिर धीरे-धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, इसके बाद दूसरी ओर दोहराएं।

**ग्लूट ब्रिज:** एनसीबीआई के अनुसार ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मजबूत होने से कमर पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम हो सकता है। इसके करने के लिए आप पीठ के बल लेटें और घुटने मोड़ें। साथ ही, पैरों को जमीन पर रखें। अब कूल्हों को ऊपर उठाएं। शरीर को घुटनों से कंधों तक सीधी लाइन में रखें। करीब 5 सेकंड तक बॉडी को होल्ड करें फिर नॉर्मल पोजीशन में आएं।

**कोबरा स्ट्रेच:** स्पाइन फाउंडेशन के अनुसार यह स्ट्रेच रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने, छाती खोलने और लंबे समय तक बैठने से होने वाली जकड़न कम करने में मदद कर सकता है। इसे करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं। अब हथेलियां को कंधों के पास रखें। धीरे-धीरे ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं। कमर पर जोर न डालें। इस पोजीशन में आप करीब 10-20 सेकंड रुकें। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। यदि दर्द लगातार बना रहे, चोट लगी हो या कोई गंभीर स्पाइनल समस्या हो, तो व्यायाम शुरू करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।

**निशाना**

## 'पानी'

**कुमार अखिलेश**

बादलों में जो मचल रहा पानी है,
जमीं पर वही उछल रहा पानी है।
कुदरत का कहर देखिए चारों तरफ,
कैसे सब कुछ निगल रहा पानी है।
नफरतों से जो पत्थर बन गया है,
मुहब्बतों से पिघल रहा पानी है।
इतनी आग समाई है उसके अंदर,
की आँसूओं में जल रहा पानी है।
पानी से जन्मे है,पानी में मिल जायेंगे,
मिट्टी को पानी में बदल रहा पानी है।
आँसूओं से कर रहें हो जो पश्चाताप,
तुम्हारे पाप को धुल रहा पानी है।
चेहरे पर तुम्हारे जो चमक आ रही है,
मुहब्बत का अंदर घुल रहा पानी है।
इसी से तुम्हारी कद की पहचान होगी,
ज़मीर में तुम्हारे जो पल रहा पानी है।

**पर्सनल फायनेंस**

# एक ही एफडी में मोटी रकम लगाना समझदारी नहीं, बीमा कवर में भी नुक्सान

**जब** आप 10 से 15 लाख रुपये जैसी बड़ी राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने की योजना बनाते हैं, तो सिर्फ उच्चतम ब्याज दर चुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही रणनीति अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छोटे प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पर अधिक ब्याज दर की पेशकश करते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी थोड़ा अधिक होता है। इसके अलावा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत प्रति बैंक केवल 5 लाख रुपये तक का ही बीमा कवर मिलता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स के अनुसार पूरी राशि को एक ही एफडी में रखने के बजाय अलग-अलग एफडी में बांटना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।

अगर आप पूरी 15 लाख रुपये की राशि एक ही एफडी में जमा करते हैं और अचानक 2 लाख रुपये की इमरजेंसी पड़ती है, तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी, जिससे ब्याज का नुकसान और पेनाल्टी झेलनी पड़ती है। 5-5 लाख रुपये की 3 अलग एफडी बनाकर रखने पर आप जरूरत के हिसाब से सिर्फ एक एफडी को मैच्योरिटी से पहले भुना सकते हैं, जबकि बाकी 2 एफडी बिना किसी रुकावट के ब्याज कमाती रहेंगी। एफडी लेडरिंग रणनीति के तहत निवेशक अपनी राशि को अलग-अलग मैच्योरिटी अवधि वाली एफडी में बांट देते हैं। उदाहरण के लिए, 10 लाख रुपये को 2-साल और 5-साल की अवधि वाली दो 5-5 लाख रुपये की एफडी में बांटा जा सकता है। जब 2 साल वाली एफडी मैच्योर होगी, तब आप उस समय की ऊंची ब्याज दरों पर उस पैसे को फिर से री-इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई का नियम कहता है कि एक बैंक में प्रति जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपये तक (मूलधन + ब्याज) ही बीमित होता है। अगर आपके पास 15 लाख रुपये हैं, तो इसे 3 अलग-अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपये की एफडी के रूप में रखकर आप अपनी पूरी 15 लाख रुपये की रकम को पूर्ण सुरक्षा के दायरे में ला सकते हैं।

**लक्ष्य-आधारित निवेश:** अलग-अलग एफडी को जीवन के विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। एक एफडी को बच्चों की पढ़ाई, दूसरी को इमरजेंसी फंड और तीसरी को किसी नियोजित खरीदारी के लिए चिन्हित किया जा सकता है। इससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है।

**अजब - गजब**

# भारतीय मूल के अरबपति ने उठाया सुनसान रहस्यमयी शहर को फिर आबाद करने का जिम्मा

**दुनियाभर** में कई ऐसे छोटे शहर और गांव हैं, जहां अब कोई नहीं रहता है। वीरान होने की वजह से इन जगहों को भूतिया शहर (Ghost Town) का दर्जा मिल जाता है। जब भी कोई ऐसी जगहों के बारे में बात करता है, तो दिमाग में टूटती-फूटती इमारतें, धूल से सने फर्श और घास-फूस से घिरी जगह की तस्वीर उभरती है। लेकिन कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के समंदर किनारे एक ऐसा रहस्यमयी शहर मौजूद है, जो इस सोच को झुठला देता है। हम बात कर रहे हैं कितसॉल्ट की, जहां पिछले 44 सालों से कोई नहीं रहता है। लेकिन इस शहर में चमचमाते मकान, शॉपिंग सेंटर, बैंक, रेस्टोरेंट, अस्पताल और थिएटर सब कुछ मौजूद है। सड़कें एकदम चकाचक हैं, गार्डन की घास कटी हुई है और रात होते ही पूरे शहर की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें अपने आप जगमगाने लगती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यहां कोई रहता नहीं, तो ये लाइटें रात में आखिर कैसे घरों और सड़कों को रौशन करती हैं?

दरअसल, अमेरिका की एक बड़ी माइनिंग कंपनी ने मोलिब्डेनम नाम की एक धातु के खनन के लिए जंगलों और पहाड़ों के बीच 1979 में इस हाई-टेक शहर को रातों-रात बसाया था। मोलिब्डेनम का इस्तेमाल लोहे और स्टील को मजबूत व जंग-रोधी बनाने के लिए किया जाता है। इसे बसाने के लिए उस दौर में पानी की तरह पैसा बहाया गया। 100 से ज्यादा मकान, 7 बड़े अपार्टमेंट, अस्पताल, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, केबल टीवी नेटवर्क और सीवेज सिस्टम बनाया गया था। पूरे उत्तर अमेरिका से इंजीनियर और मजदूर भारी सैलरी के लालच में यहां आकर बसे और देखते ही देखते 1,200 से अधिक लोगों से यह शहर गुलजार हो गया था। लेकिन इसकी रौनक ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकीं। पहला परिवार बसने के महज 18 महीने बाद ही मंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मोलिब्डेनम की कीमतें अचानक नीचे गिर गईं।

घाटा इतना बढ़ गया कि खदानों को रातों-रात बंद करना पड़ा। काम बंद होते ही यहां रहने वाले लोग धीरे-धीरे शहर छोड़कर चले गए और साल 1982 तक यह पूरा का पूरा शहर खाली हो गया। इसके बाद साल 2005 में भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कृष्णन सुथंतिरन की नजर इस खाली पड़े शहर पर पड़ी। उन्होंने इसे लगभग 58 करोड़ रुपये खरीद लिया। तब से लेकर अब तक वे इस शहर की देखभाल पर लगभग 200 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हैं। उन्होंने इस शहर को साफ-सुथरा और नया बनाए रखने के एक टीम तैनात कर रखी है।

## न्यूज विंडो

### त्योंदा में 119 लोगों कराया निशुल्क ब्लड ग्रुप परीक्षण

**गंजबासौदा।** मानव सेवा के संकल्प को साकार करने और रक्तदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम त्योंदा में रक्त सेवा समिति के तत्वावधान में निःशुल्क रक्त समूह परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों, युवाओं एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनभर चले इस शिविर में 119 लोगों ने अपना रक्त समूह परीक्षण कराया और रक्तदान के महत्व की जानकारी प्राप्त की। शिविर का उद्देश्य लोगों को अपने रक्त समूह की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह संदेश देना था कि आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर रक्त उपलब्ध होना किसी भी जरूरतमंद के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। समिति के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित लोगों को नियमित स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि एक यूनिट रक्त कई जिंदगियों को बचाने में सहायक बन सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं रक्त सेवा समिति के संस्थापक राजेश तिवारी ने कहा कि समाज सेवा का सबसे श्रेष्ठ माध्यम रक्तदान है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी मरीज को रक्त के अभाव में परेशानी का सामना न करना पड़े।

### रिटायर्ड शिक्षिका से लिफ्ट लगाने के नाम पर 4 लाख की ठगी, केस दर्ज

**नर्मदापुरम।** शहर के कालिकानगर निवासी 73 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका से लिफ्ट लगाने के नाम पर 4 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। एडवांस राशि लेने के बावजूद कंपनी ने न तो लिफ्ट लगाई और न ही राशि लौटाई। परेशान बुजुर्ग महिला अपने दिव्यांग बेटे को व्हीलचेयर पर लेकर कोतवाली थाने पहुंचीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कंपनी संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता दीपाली शर्मा ने बताया कि वह अपने दिव्यांग बेटे के साथ रहती हैं। बारिश के दौरान घर में पानी भर जाने से बेटे को बाहर ले जाने में काफी परेशानी होती है। इसी कारण उन्होंने मकान में पहली मंजिल बनवाकर लिफ्ट लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए भोपाल स्थित सेल्को लिफ्ट एंड एक्सीलेटर कंपनी के संचालक मनीष मिश्रा से संपर्क किया था। दीपाली शर्मा के अनुसार लिफ्ट लगाने के लिए 7 लाख रुपए में अनुबंध हुआ था। इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 को 1 लाख, 31 अक्टूबर 2025 को 2 लाख तथा 24 जून 2026 को 1 लाख रुपए, कुल 4 लाख रुपए एडवांस के रूप में कंपनी को दिए गए। कंपनी ने आश्वासन दिया था कि मकान का निर्माण और पुताई पूरी होने के बाद लिफ्ट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। करीब 20 दिन पहले मकान तैयार हो गया, लेकिन अब कंपनी काम करने से इंकार कर रही है और एडवांस राशि भी वापस नहीं कर रही। राशि वापस नहीं मिलने पर दीपाली शर्मा अपने दिव्यांग बेटे के साथ कोतवाली थाना पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली के एसआई वंशज श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कंपनी से संपर्क किया गया था।

### रंगदारी और गुंडागर्दी के आरोपी को पुलिस ने सड़कों पर घुमाया

**धार।** जिले के राजगढ़ में पुलिस ने रंगदारी और गुंडागर्दी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर कस्बे में उसका जुलूस निकाला। पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी को मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों से पैदल घुमाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। पुलिस के अनुसार, ग्राम अमोदिया निवासी हिम्मत पिता लक्ष्मण सेप्टा पर अपने साथियों के साथ मिलकर राजगढ़ क्षेत्र में रंगदारी दिखाने और मारपीट करने का आरोप है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कस्बे के प्रमुख बाजारों और मार्गों से पैदल घुमाकर यह संदेश दिया गया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि क्षेत्र में रंगदारी, हफ्ता वसूली, मारपीट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि अपराधियों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम रखना पुलिस की प्राथमिकता है।

### प्रीति माहेश्वरी फिर बनीं धार महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष

**धार।** मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया के नेतृत्व में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अनुशंसा पर धार जिले की कमान एक बार फिर प्रीति माहेश्वरी को सौंपी गई है। लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी ने संगठनात्मक अनुभव और सक्रियता को देखते हुए प्रीति माहेश्वरी पर फिर भरोसा जताया है। नियुक्ति की घोषणा होते ही धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी, संगठन मंत्री परितोष बना, विधायक भंवर सिंह शेखावत, सुरेंद्र सिंह बघेल, प्रताप ग्रेवाल, हीरालाल अलावा, लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल, प्रदेश सचिव सोहेल निसार, हरदेव सिंह जाट, पूर्व विधायक पांचीलाल मेडा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित कामदार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कृष्णा पवार सेवादल जिला अध्यक्ष जितेंद्र जोशी प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी, सोशल मीडिया विभाग जिला अध्यक्ष प्रिंस ठाकुर सहित जिले के कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रीति माहेश्वरी को बधाई दी और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं



## अशोकनगर जिले के मुंगावली का मामला

# 27 साल तक डॉक्टर-टीचर बनकर काटता रहा मौज, एक धमकी ने खोल दी पोल

**अशोकनगर। दोपहर मेट्रो**

फिल्मी कहानियों को मात देने वाला सनसनीखेज मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली से सामने आया है। दिल्ली व हरियाणा में हत्या, बलवा, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराधों में पिछले 27 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा हरियाणा का अपराधी यहां सामान्य नागरिक की तरह रह रहा था। नाम, जाति और पहचान बदलकर उसने न सिर्फ एक एएनएम से लव मैरिज की, बल्कि बिना डिग्री के डॉक्टर और स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर तक बन गया। जिसे पुलिस गिरफ्तार किया है।

दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंगावली पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर गांधीनगर का निवासी राजिंदर बारागी पुत्र सूरजमल पर वर्ष 1997 में दिल्ली के जनकपुरी थाने में हत्या के प्रयास के दो मामले दर्ज हुए। वहीं हरियाणा के गन्नौर थाने में 1998 में ही बलवा, हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर अपराध दर्ज थे। वर्ष 1999 में वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर एक और मामला दर्ज हुआ। 29 फरवरी 2008 को दिल्ली के रोहिणी न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

जब वह भागा था तब उसकी उम्र 26 साल थी और आज 53 साल की उम्र में वह पुलिस की गिरफ्त में आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, वह कई सालों से नाम, जाति और पहचान बदलकर यहां रह रहा था। जिसे क्राइम ब्रांच की टीम न्यायालय में पेश करने के बाद अपने साथ दिल्ली ले गई और वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

#### ऐसे खुला राज: एक धमकी और पहुंच गई क्राइम ब्रांच

27 साल से बेखौफ जिंदगी जी रहे इस अपराधी का पर्दाफाश एक जमीनी विवाद के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि जमीन के एक मामले में उसने अपने ही किसी रिश्तेदार को धमकी दे डाली। रिश्तेदार को इसकी असलियत पता थी जिसने दिल्ली क्राइम ब्रांच को इसकी सटीक लोकेशन की टिम दे दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मंगलवार को मुंगावली पहुंची और स्थानीय थाना प्रभारी अरविंद सिंह की मदद से आरोपी को धर दबोचा।

#### बहरूपिए की जिंदगी: राजिंदर से ऐसे बना राजेंद्र सिंह यादव

पुलिस के मुताबिक राजिंदर शुरुआत में करीब दो साल मुंबई में रहा और सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम किया, जिसका सिक्योरिटी गार्ड का आइकार्ड भी मिला है। इसके बाद वह मध्यप्रदेश के मुंगावली आ गया। यहां उसने अपनी पहचान मिटा दी और राजिंदर बारानी से राजेंद्र सिंह यादव बन गया। शिवपुरी निवासी ममता यादव से लव मैरिज कर ली। ममता यादव स्वास्थ्य विभाग में एएनएम है और मुंगावली के मवऊखेड़ी गांव में पदस्थ है। पत्नी के साथ रहकर उसने इलाज की बारीकियां सीखीं और बिना किसी डिग्री के डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने लगा। इतना ही नहीं. वह केंद्रीय विद्यालय सहित कई प्राइवेट स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में भी काम कर चुका था।

### बस हेल्पर को पीटा, कोतवाली पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार

**धार। दोपहर मेट्रो**

शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। धार्मिक स्थल के पास पेशाब करने से मना करने पर मनबढ़ बदमाशों ने एक बस हेल्पर पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। वहीं, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फरियादी सुनील पिता मानसिंह परमार (निवासी कलारिया, चंदननगर, इंदौर) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे शुभम बस का हेल्पर अशोक केवट बस की सफाई कर रहा था। इसी दौरान एक युवक बस स्टैंड स्थित भैरूबाबा मंदिर के पास पेशाब करने लगा। हेल्पर अशोक ने जब मंदिर परिसर के पास ऐसा करने से मना किया, तो वह युवक और उसका साथी आक्रोशित हो गए। अनावेदकों ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए अशोक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने लात-घूंसों के साथ हाथ में पहने लोहे/धातु के कड़े से अशोक के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस बल मौके पर पहुँचा। घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय धार ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ऋतिक पिता रामनाथ मर्सकोले, राहुल पिता मंगलसिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

### बेटे का खूनी खेल, घरेलू विवाद में पिता को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला, मां घायल

**शहडोल। दोपहर मेट्रो**

जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने मामूली घरेलू विवाद में अपने ही पिता की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आई मां पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान दऊआ बैगा (50) के रूप में हुई है। बताया गया कि दऊआ और उनकी पत्नी यशोदा मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। सुबह दोनों घर लौटे। घर पहुंचने के बाद दऊआ ने भोजन करने की इच्छा जताई। इस पर यशोदा खाना बनाने लगी लेकिन घर में मौजूद उनका पुत्र अंजू इस बात पर भड़क गया और कहने लगा कि वह स्वयं खाना बनाकर माता-पिता को खिलाएगा। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पहले अपनी मां यशोदा के साथ मारपीट शुरू कर दी। मां को बचाने के लिए जब पिता दऊआ बीच में आए तो आरोपी ने लाठी से उनके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से दऊआ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल दंपती को तत्काल जयसिंहनगर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में यशोदा का उपचार जारी है, जबकि गंभीर रूप से घायल दऊआ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही जयसिंहनगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी अजय कुमार बैगा ने बताया कि आरोपी पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घरेलू विवाद में हुई इस हत्या से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

### श्री महाराणा प्रताप राजपूत समिति ने किया कृषि मंत्री और विधायक का अभिनन्दन

**गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो**

श्री महाराणा प्रताप राजपूत समिति के तत्वावधान में बासौदा क्षेत्र के राजपूत समाज ने भोपाल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा क्षेत्रीय विधायक हर सिंह रघुवंशी का भव्य नागरिक अभिनंदन कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

यह सम्मान समारोह राजपूत समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सांसद निधि तथा विधायक हरिसिंह रघुवंशी द्वारा विधायक निधि से राशि स्वीकृत कराए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्र के सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह जादौन के नेतृत्व में समाज का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री

शिवराज सिंह चौहान का स्वाफा पहनाकर, शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, गजरा एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर आत्मीय सम्मान किया गया। वहीं क्षेत्र के विकास और समाजहित में किए जा रहे कार्यों के लिए विधायक हरि सिंह रघुवंशी को भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

समारोह में समाज के अध्यक्ष ठाकुर प्रवीण प्रताप सिंह जादौन, महासचिव प्रमोद सिंह राजपूत, पूर्व अध्यक्ष चंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह (मनुजी), जगदीप सिंह, अमान सिंह, सीबी सिंह, विनोद राठौर, मुकेश सिंह, जगदीश सिंह, किशोर सिसोदिया, शैलेंद्र राठौड़, रूप सिंह, अखिलेश सिंह, निरंजन सिंह, किशोर भदौरिया, सतनाम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, वीर बहादुर सिंह, राजपाल सिंह, जितेंद्र आटासेमर, संतोष सिंह, राजवीर सिंह, बहादुर सिंह निचरोन, प्रेम सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे।

### पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

**धार। दोपहर मेट्रो**

शहर के थाना कोतवाली अंतर्गत बस स्टैंड क्षेत्र में 14 जुलाई की रात हुए जानलेवा हमले और जातिसूचक हिंसा के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को वैधानिक प्रक्रिया के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फरियादी ऋतिक (22) पिता सुरेश वाघेला, निवासी रैदास मार्ग, बस स्टैंड धार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि 14 जुलाई की रात लगभग 10:45 बजे बस स्टैंड स्थित इमली के पेड़ के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अबुल और उसके साथियों ने उसे अचानक घेर लिया। इस दौरान मुख्य आरोपी अबुल ने जान से मारने की नीयत से लोहे की टामी से ऋतिक के सिर, सीने, पीठ और हाथों पर ताबड़तोड़ वार किए। वहीं उसके अन्य साथियों ने भी फरियादी के साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट की। घटना में गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली सटीक सूचना के आधार पर दबिश देकर मामले में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद नवाब उर्फ बाबू पिता कासम, सुल्तान खान उर्फ इरशाद पिता रियाज खान, मोहम्मद अहमद उर्फ शाहिल पिता रोशन अली, मोहम्मद पिता मोहम्मद हनीफ, सलमान पिता आलेनूर, मोहम्मद हुसैन उर्फ अल्तमस पिता अल्लाह हुसैन को गिरफ्तार किया है।

## मेट्रो एंकर

### खेड़ापति गौधाम में पार्थिव शिवलिंग निर्माण महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

# अहंकार त्याग कर आत्मचिंतन करें, तभी मिलेगा अमृत रूपी ज्ञान: धर्मेंद्र भार्गव

**गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो**

श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री राम-जानकी मंदिर, खेड़ापति गौधाम में आयोजित 27 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं भगवान शिव के 84 अवतार चरित्र वर्णन महोत्सव के छठे दिवस भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार का भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी वर्णन किया गया। शिव कथा वाचक पं. धर्मेन्द्र भार्गव ने समुद्र मंथन प्रसंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन, विनम्रता एवं शिवभक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं को अमृत सहित अनेक दिव्य रत्न प्राप्त हुए तो उनमें अहंकार उत्पन्न हो गया। देवताओं के इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने यक्षेश्वर रूप धारण किया। अग्निदेव और वायुदेव जैसे महाशक्तिशाली देवता भी उस दिव्य यक्ष के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय नहीं दे सके। तब उन्हें अनुभूति हुई कि समस्त शक्ति, ज्ञान और विजय का

मूल आधार भगवान शिव की कृपा ही है। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति कर उनसे क्षमा याचना की। पं. भार्गव ने समुद्र मंथन के आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन करते हुए कहा कि समुद्र केवल क्षीरसागर नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का मन भी एक अथाह समुद्र है। इस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे विष भी मौजूद हैं, वहीं प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, विवेक, ज्ञान और आत्मबोध रूपी अमृत भी छिपा हुआ है। जब मनुष्य सत्संग, जप, तप, स्वाध्याय और शिवभक्ति के माध्यम से अपने मन का मंथन करता है, तब सबसे पहले उसके भीतर छिपे विकार सामने आते हैं। जो साधक भगवान शिव की कृपा से इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में शांति, ज्ञान और आनंद रूपी अमृत का उदय होता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का यक्षेश्वर अवतार हमें अहंकार का त्याग, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की प्रेरणा देता है। मन का मंथन किए बिना जीवन में अमृत रूपी ज्ञान और आत्मिक आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के दोषों को पहचानकर शिवभक्ति के माध्यम से स्वयं को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। कथा के उपरांत श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण, भगवान शिव का अभिषेक, पूजन एवं महाआरती में भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा और श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर दिखाई दिए।

# रास्ते के विवाद पर ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू, कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा आक्रोश

**तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो**

जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारसबगली में सार्वजनिक रास्ते को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को कई बार शिकायत, आवेदन और ज्ञापन सौंपने के बावजूद सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार गांव के सार्वजनिक उपयोग के रास्ते पर कथित अतिक्रमण होने से लोगों के आवागमन में लगातार परेशानी हो रही है। इस संबंध में पहले स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की। कलेक्टर के निर्देश पर तहसील कार्यालय में मामले की

सुनवाई हुई थी।

सुनवाई के दौरान तहसीलदार विवेक व्यास ने राजस्व अमले से प्रतिवेदन प्राप्त कर सीमांकन एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि अंतिम निर्णय होने तक किसी भी स्थिति में सार्वजनिक रास्ता बंद नहीं होने दिया जाएगा तथा संबंधित भूमि स्वामी को भी मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से आमरण अनशन जैसे कदम नहीं उठाने की अपील करते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन दिए जाने के लगभग एक सप्ताह बाद भी प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से आमरण अनशन शुरू करने का निर्णय लिया।

अनशन पर बैठे ग्रामीणों में दशरथ यादव, कमलेश पटेल, शुभम यादव और भगीरथ रजक सहित अन्य ग्रामीण जन प्रमुख रूप से शामिल हैं। भगीरथ रजक ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर और तहसीलदार को पहले ही अवगत करा दिया था उन्होंने कहा था की रास्ता बंद नहीं होने देंगे। हम लोगों ने कहा था कि यदि एक सप्ताह के भीतर रास्ता नहीं खुला तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण सोमवार दोपहर 12 बजे से ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं और जब तक सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाकर आवागमन पूरी तरह सुचारु नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दशरथ यादव का कहना है कि यह मार्ग लगभग 100 वर्षों से आम रास्ता बना हुआ है लेकिन एक व्यक्ति द्वारा जमीन खरीद लेने से उसने आम रास्ता बंद कर दिया है जिसका हम ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई करने तथा सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल एक रास्ते का नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों के आवागमन और उनके अधिकारों से जुड़ा मामला है। तहसीलदार विवेक व्यास ने बताया कि ग्राम वासियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन ग्रामवासी वही रास्ता चाहते हैं जो पहले से बना हुआ है जबकि उक्त भूमि एक निजी भूमि है जिसके कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है फिर भी इस संबंध में ग्राम पंचायत से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव मांगा गया है उसके बाद ही देखते हैं क्या हो सकता है।

## न्यूज विंडो

### अमरकंटक में लीज भूमि पर निर्माण को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग

**अमरकंटक।** पवित्र नगरी अमरकंटक में भूमि उपयोग एवं निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को लेकर एक नया मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के पुष्पराजगढ़ विधानसभा अध्यक्ष हितेश तंबोली (बिरू) ने नगर परिषद अमरकंटक के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर होटल अमरकंटक इन द्वारा लीज भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि संबंधित भूमि की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, जबकि वहां निर्माण एवं विस्तार कार्य जारी है। इस संबंध में अभिलेखीय स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मामले की विधिवत जांच आवश्यक बताई गई है, ताकि वास्तविक तथ्यों का पता चल सके और जनसामान्य के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो सके। युवा कांग्रेस नेता ने अपने आवेदन में मांग की है कि संबंधित भूमि की वर्तमान लीज की वैधता का अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कराया जाए। यदि लीज अवधि समाप्त हो चुकी हो तो यह भी जांच की जाए कि निर्माण कार्य किस वैधानिक आधार पर किया जा रहा है। साथ ही भवन निर्माण की स्वीकृति, स्वीकृत नक्शा तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों का भी परीक्षण किया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा जांच प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई से आवेदक को अवगत कराया जाए।

### प्रशिक्षण शिविर में जनभागीदारी एवं सामाजिक सरोकारों पर दिया मार्गदर्शन

**तेंदूखेड़ा।** मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की संवाद योजना अंतर्गत प्रस्फुटन शक्ति संचय कार्यक्रम के तहत विकासखंड स्तरीय मासिक बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा के सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में प्रस्फुटन समितियों के अध्यक्षों, सचिवों, नवांकुर संस्थाओं एवं परामर्शदाताओं को ग्राम विकास, जनभागीदारी, सामाजिक दायित्व तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम एवं प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत सी. पी. गोस्वामी ने कहा कि ग्राम विकास में जनसहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्फुटन समितियां शासन और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में प्रभावी योगदान दे सकती हैं। उन्होंने समितियों से सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सुशील नामदेव ने प्रस्फुटन समितियों के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समाजहित के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ग्राम स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया। बैठक के दौरान ग्रामीण विकास समिति के कार्यक्रम संगठक धरमदास पाल ने जानकारी दी कि तेंदूखेड़ा में कटे होंठ एवं कटे तालु से पीड़ित बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए निःशुल्क जांच एवं उपचार शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित अध्यक्षों एवं सचिवों से अपील की कि ऐसे जरूरतमंद मरीजों की पहचान कर उन्हें शिविर तक पहुँचाने में सहयोग करें, ताकि वे निःशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त कर सकें।

### युवक का शव मिलने के बाद गांव में बवाल, परिजनों ने पुलिस पर किया पथराव

# 1 अगस्त की रात घर से निकला था अतुल, झाड़ियों में बोरी में मिला शव

**सतना। दोपहर मेट्रो**

जिले के जसो थाना क्षेत्र के अमकुई गांव में मंगलवार को एक युवक का शव मिलने के बाद बवाल मच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम पर मृतक के परिजनों व गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ की। युवक तीन दिनों से लापता था और उसका शव गांव में एक स्कूल के पीछे झाड़ियों में बोरी में लिपटा हुआ मिला है। पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इधर गांव में माहौल तनावपूर्ण होने के कारण भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

अमकुई गांव का रहने वाला 20 वर्षीय अतुल कुशवाहा 1 अगस्त की रात करीब 9.30 बजे घर से निकला था। काफी देर तक जब अतुल वापस घर नहीं आया तो परिजन ने उसके मोबाइल फोन कॉल किया। मोबाइल बंद जा रहा था जिसके कारण परिजनों को चिंता हुई और परिजन ने अतुल की तलाश शुरू की। परिजन के मुताबिक अतुल के कहीं न मिलने पर वो गुमशुदगी दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 4 अगस्त को गांव में स्कूल के पीछे झाड़ियों में बोरी में अतुल का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। अतुल का शव मिलने की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जब पुलिस मौके

पर पहुंची तो परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। गांव में हालात बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और वज्र वाहन तैनात करना पड़ा और करीब साढ़े 4 घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

#### संदेही हिरासत में, लड़की से जुड़े विवाद की बात आई सामने

पुलिस ने एक संदेही युवक को भी हिरासत में लिया है, संदेही से पता चला है कि एक लड़की से बातचीत को लेकर उसका व साथियों का अतुल से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। हंगामे के बीच संदेही ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि 1 अगस्त की रात को संदेही ने ही अतुल को घर से बुलाया था और सभी ने साथ में बैठकर शराब पी थी। शुरुआती जांच में ये बात भी पता चली है कि अतुल कुशवाहा की जसो में मोबाइल की दुकान है और उसने 1 अगस्त को ही बैंक से 3 लाख रुपये निकाले थे, इनमें से दो लाख रुपये उसने घर में रखे थे और 1 लाख रुपये दुकान में रखे थे।

### 8 माह बाद भी वार्ड-13 में चुनाव नहीं नियमों पर भारी प्रशासनिक सुस्ती!

**कोतमा। दोपहर मेट्रो**

नगर पालिका कोतमा के वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद पद रिक्त हुए आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होने का मामला सामने आया है। इससे वार्ड के मतदाताओं में नाराजगी है और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19(4) में प्रावधान है कि यदि किसी वार्ड में पार्षद का निर्वाचन नहीं हो पाता है तो उस वार्ड की सीट भरने के लिए छह माह के भीतर नई चुनाव प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

ऐसे में सवाल यह है कि जब वार्ड क्रमांक 13 में आठ महीने से अधिक समय बीत चुका है, तो अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई? क्या जिला प्रशासन और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने शासन के प्रावधानों के अनुरूप समयसीमा में कार्रवाई की? पार्षद के अभाव में वार्डवासियों को अपनी स्थानीय समस्याएं और विकास संबंधी मांगें उचित प्रतिनिधि के माध्यम से नगर पालिका परिषद में रखने में कठिनाई हो सकती है। लंबे समय तक निर्वाचित प्रतिनिधि का पद रिक्त रहना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय निकाय व्यवस्था की भावना पर भी सवाल खड़ा करता है। आठ महीने बीतने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर अब जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि वार्ड क्रमांक13 में चुनाव कराने की कार्रवाई किस स्तर पर लंबित है, देरी का कारण क्या है और चुनाव प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जाएगी। यदि किसी कानूनी अथवा प्रशासनिक कारण से देरी हुई है तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

### खाद वितरण व्यवस्था में सुधार, पुलिस निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से वितरण

**तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो**

खाद वितरण को लेकर सोमवार को बनी अव्यवस्था के बाद प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए खाद वितरण कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराया। पुलिस बल की मौजूदगी और प्रशासनिक निगरानी के बीच कृषि उपज मंडी स्थित डबल लॉक गोदाम से किसानों को डीएपी एवं यूरिया खाद का वितरण शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की धक्का-मुक्की या विवाद की स्थिति नहीं बनी।

खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ने के कारण अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसके बाद व्यवस्था सुधारने के लिए कूपन योजना लागू करने की तैयारी की गई थी। इसके तहत ग्राम पंचायत सचिवों को सुबह 7 बजे जनपद पंचायत कार्यालय बुलाया गया था, ताकि उनके माध्यम से किसानों को कूपन वितरित कर खाद वितरण को व्यवस्थित किया जा सके। जनपद पंचायत के निर्देश पर सचिव निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंच गए, लेकिन जिला स्तर से कूपन वितरण की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण योजना को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान सचिवों को लगभग चार घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तहसीलदार से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि जिला

कलेक्टर स्तर से अनुमति नहीं मिलने के कारण कूपन व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। सुबह लगभग 10:30 बजे से डीएपी एवं यूरिया खाद इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में खाद वितरण शुरू किया गया। गोदाम परिसर में पुरुष और महिला किसानों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं। किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उन्हें खाद उपलब्ध कराया गया। खाद वितरण व्यवस्था के कूपन जारी करने के लिए लिए जनपद पंचायत से सचिवों और रोजगार सहायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसके कारण सुबह 7 बजे कमल नारायण यादव, घनश्याम विश्वकर्मा, भूपत सिंह यादव, रामकुमार पाल, भगवानदास यादव सहित जीआरएस राजेंद्र केवट, रामकिशन यादव और महेंद्र उसरेठे, कोमल यादव जनपद पहुंचे 10 बजे तक जनपद में रहे लेकिन उन्हें कूपन प्राप्त ही नहीं हुये सुबह लगभग 10:30 बजे डबल लाक दमोह से वज्र वाहन में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और पूरी व्यवस्था संभाली। एसडीओपी अर्चना अहीर लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करती रहीं। पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के कारण खाद वितरण कार्य शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा और किसानों को बिना परेशानी के खाद प्राप्त हुई। किसानों ने मंगलवार की व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि कतारबद्ध तरीके और दस्तावेज सत्यापन के कारण उन्हें बिना धक्का-मुक्की के खाद मिल गई। वहीं प्रशासन ने भी किसानों से अपील की है कि वे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।किसानों का कहना है कि डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

## मेट्रो एंकर

### बुंदेलखंड के यात्रियों का इंतजार आखिर हुआ खत्म

# बुंदेलखंड के लाखों यात्रियों को सौगात, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के लिए नई स्पेशल ट्रेन शुरू

**छतरपुर। दोपहर मेट्रो**

बुंदेलखंड के रेल यात्रियों के लिए आज का दिन एक नई और बड़ी सौगात लेकर आया है। लंबे समय से दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे क्षेत्रवासियो की मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज से बेंगलुरु (यशवंतपुर) के बीच नई वीकली स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 04149/04150) चलाने का निर्णय लिया है, जो 5 अगस्त से विधिवत शुरू गई है। यह ट्रेन खजुराहो, महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर, टीकमगढ़ और ललितपुर होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से क्षेत्र के यात्रियों को पहली बार सीधे नागपुर, सिकंदराबाद और बेंगलुरु (यशवंतपुर) तक सुविधाजनक रेल सेवा मिल रही है। इस ट्रेन की शुरुआत से केवल दक्षिण भारत की यात्रा ही आसान नहीं हुई है, बल्कि भोपाल जाने वाले यात्रियों को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ट्रेन छतरपुर से रात 3: 08 बजे रवाना होकर सुबह 9:30 बजे रानी कमलापति (भोपाल) पहुंच जाएगी। इससे सरकारी काम, इलाज या व्यावसायिक कार्यों के लिए भोपाल जाने वाले यात्रियों को सुबह-सुबह पहुंचने का एक नया और समय बचाने वाला विकल्प मिल गया है।

#### 8-8 फेरे लगाएगी ट्रेन, नियमित करने की मांग

रेलवे प्रशासन ने आगामी त्योहारों और अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए फिलहाल इस वीकली स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। यह ट्रेन आज 5 अगस्त से 23 सितंबर तक प्रत्येक बुधवार (आज से शुरू होकर) चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 8 अगस्त से 26 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 8-8 फेरे लगाएगी। हालांकि, इस रूट पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय लोगों और व्यापारिक संगठनों ने अभी से इस ट्रेन को नियमित करने की मांग उठाना शुरू कर दिया है।

#### 23 कोच की होगी पूरी ट्रेन

यात्रियों की हर श्रेणी का ध्यान रखते हुए इस स्पेशल ट्रेन में कुल 23 आईसीएफ कोच लगाए गए हैं। इसमें 1 फर्स्ट / सेकंड एसी. 2 थर्ड एसी, 11 स्लीपर क्लास, 7 जनरल (अनारक्षित) कोच, 2 एसएलआर कोथ शामिल हैं।


**M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.**
(A Govt. of M.P. Undertaking)
Office of the Dy. General Manager (South) City Division, Bhopal
Second Stop, Tulsi Nagar, Bhopal, Phone : 0755-2678306
E-Mail : citysouthbpl@gmail.com
No. : DGM/CDS/PUR/2331 Bhopal, Dated : 30.07.2026

**OFFER FOR HIRING VEHICLE**

MPMKVVCL hereby invited offer/rate for hiring the below mentioned type of vehicle in the following locations.

| Name of Unit/ Office | Particulars | EMD (Rs.) | Due Date of Submission of Offer | Opening Date & Time |
|---|---|---|---|---|
| Manager Bhadbhada Zone Under City Division South, Bhopal | **Type G3 :** Light Commercial Vehicle (Non-AC) (3-5 metric Ton) Truck or Equivalent (For Single Shift) | 3000/- | 13.08.2026 Up to 3.00 P.M. | 13.08.2026 at 03.30 P.M. |

Other details, terms and conditions are available on company **website : portal.mpcz.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/127336/2026 **DGM (SOUTH), CITY DIVISION**

### आकाश चोपड़ा की चेतावनी- श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट करो या मरो जैसे

# डब्ल्यूटीसी फाइनल पर मंडराया खतरा! श्रीलंका में चूकी टीम इंडिया तो टूट जाएगा लॉर्ड्स का सपना

**नई दिल्ली, एजेंसी**

**आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के फाइनल की दौड़ अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया को बड़ा अलर्ट दिया है। उनका कहना है कि 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के लिए किसी करो या मरो मुकाबले से कम नहीं है। यदि भारतीय टीम इस सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती, तो लॉर्ड्स में होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल तक पहुंचने का सपना गंभीर संकट में पड़ सकता है।**

**अंक तालिका में बढ़ सकता है दबाव-** आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर डब्ल्यूटीसी की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत के लिए यह सीरीज सिर्फ एक द्विपक्षीय मुकाबला नहीं, बल्कि पूरे टेस्ट चक्र की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। उनके अनुसार यदि भारत श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट हार जाता है, तो उसकी प्रतिशत अंक (पीसीटी) करीब 39 तक गिर जाएगी। वहीं श्रीलंका लगभग 61 पीसीटी के साथ तालिका में मजबूत स्थिति हासिल कर लेगा और फाइनल की रेस में बड़ा दावेदार बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत के लिए वापसी करना बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि आगे का कार्यक्रम पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण है।

### बुमराह की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई मुश्किलें

### जीत से मजबूत होगी फाइनल की उम्मीद

आकाश चोपड़ा का मानना है कि यदि भारत श्रीलंका को 2-0 से हराने में सफल रहता है, तो टीम का पीसीटी बढ़कर लगभग 57.58 तक पहुंच जाएगा। इससे भारतीय टीम की फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं काफी मजबूत होंगी और आगे की कठिन सीरीज से पहले मनोबल भी बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त होती है, तो भारत को लगभग कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत का पीसीटी करीब 48.48 और श्रीलंका का 44.44 रहेगा, जिससे दोनों टीमों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

### बुमराह की चोट ने बढ़ाई चिंता

भारत की मुश्किलें सिर्फ डब्ल्यूटीसी अंक तालिका तक सीमित नहीं हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण श्रीलंका दौरे से बाहर हो चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को कमजोर कर सकती है, क्योंकि विदेशी परिस्थितियों में बुमराह टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज माने जाते हैं। ऐसे में युवा और अन्य अनुभवी गेंदबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी कि वे श्रीलंका की बल्लेबाजी को दबाव में रखें और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएं।

### आगे और कठिन है टीम इंडिया का सफर

श्रीलंका दौरे के बाद भारत को न्यूजीलैंड में दो टेस्ट मैच खेलने हैं। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में जीत हासिल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसके बाद भारत को घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की लंबी और कठिन सीरीज खेलनी होगी। आकाश चोपड़ा का मानना है कि यदि भारत श्रीलंका के खिलाफ अंक गंवा देता है, तो बाद की इन कठिन सीरीज में दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे में टीम के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह बेहद मुश्किल हो सकती है।

### हर मुकाबला बनेगा निर्णायक

डब्ल्यूटीसी के मौजूदा प्रारूप में हर टेस्ट मैच और हर जीत का सीधा असर अंक तालिका पर पड़ता है। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट अब सामान्य द्विपक्षीय सीरीज नहीं रह गए हैं, बल्कि भारत के डब्ल्यूटीसी अभियान की दिशा तय करने वाले मुकाबले बन चुके हैं। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि भारतीय टीम दबाव के बीच कैसा प्रदर्शन करती है। यदि रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम श्रीलंका में दमदार जीत दर्ज करती है तो फाइनल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, लेकिन एक भी बड़ी चूक भारत के लिए लॉर्ड्स पहुंचने का सपना अधूरा छोड़ सकती है।

### स्वर्णिम सफलता का भव्य सम्मान

# भारत लौटे कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनों का एयरपोर्ट पर हुआ ऐतिहासिक स्वागत

**नई दिल्ली, एजेंसी**

कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मंगलवार को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और भारत माता के जयघोष के बीच खिलाड़ियों का अभिनंदन हुआ। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, परिवार के सदस्य, खेल अधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने इस आत्मीय सम्मान के लिए देशवासियों का आभार जताते हुए कहा कि यह पल उनके जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 96 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत ने मुक्केबाजी में सात स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

### खिलाड़ियों ने देश को समर्पित की जीत

स्वर्ण पदक विजेता साक्षी चौधरी ने कहा कि एयरपोर्ट पर मिला प्यार और सम्मान उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। उन्होंने अपनी जीत देशवासियों को समर्पित करते हुए भारत सरकार, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के सहयोग को सफलता की बड़ी वजह बताया। साक्षी ने कहा कि भविष्य में भी उनका लक्ष्य देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतना रहेगा। उनके दादा सतपाल सिंह ने कहा कि साक्षी की उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने युवाओं से मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की अपील की।

# PL को लेकर आमिर ने तोड़ी चुप्पी वायरल वीडियो में दिया बड़ा संकेत

**नई दिल्ली, एजेंसी**

सोशल मीडिया पर इन दिनों पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आमिर से आईपीएल में खेलने की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी। वायरल वीडियो में आमिर कहते हैं, मैं 2027 में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में ओवरसीज खिलाड़ी के तौर पर खेलूंगा। जहां तक आईपीएल की बात है, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। आमिर का यह बयान ऐसे समय आया है जब ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद उनके आईपीएल में खेलने की संभावनाओं को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, उन्होंने फिलहाल किसी भी तरह की पुष्टि या इनकार नहीं किया है।

मोहम्मद आमिर को हाल ही में ब्रिटिश नागरिकता मिली है। उनकी पत्नी ब्रिटेन की नागरिक हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आमिर भी ब्रिटिश नागरिक बन गए। इसके बाद इंग्लैंड की घरेलू टी20

प्रतियोगिताओं में उनका दर्जा बदल गया है। वह टी20 ब्लास्ट में नॉट्स आउटलॉज और द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए स्थानीय खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं। अब उन्हें इंग्लिश क्रिकेट में विदेशी खिलाड़ी (ओवरसीज) नहीं माना जाता।

ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि क्या आमिर भविष्य में आईपीएल का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, वायरल वीडियो में उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उन्होंने आईपीएल को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है।

### भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया महिला ए टीम का हुआ ऐलान

**मेलबर्न।** भारत दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम का एलान कर दिया है। 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन और टायला व्लामिन्क की वापसी सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों खिलाड़ी लंबे समय बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौट रही हैं और भारतीय परिस्थितियों में अपनी छाप

छोड़ने के लिए तैयार हैं। चयनकर्ताओं का मानना है कि इन अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से युवा प्रतिभाओं को सीखने और निखरने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। 27 वर्षीय टायला व्लामिन्क पिछले टी20 विश्व कप के दौरान कंधे की चोट के कारण टीम से बाहर हो गई थीं। अब पूरी तरह फिट होने के बाद उनकी वापसी हुई है और वह भारत के खिलाफ अपनी रफ्तार और अनुभव का दम दिखाने के लिए उत्साहित हैं। वहीं 23 वर्षीय डार्सी ब्राउन को टी20 विश्व कप टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन भारत दौरे के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए में शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि उनका अनुभव टीम के प्रदर्शन को मजबूती देगा।

### सिनसिनाटी ओपन में फिर साथ दिखेंगी विलियम्स बहनें

# यूएस ओपन से पहले खेलेंगी डबल्स गेम्स

**नई दिल्ली, एजेंसी**

सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स एक बार फिर डबल्स कोर्ट पर साथ उतरने के लिए तैयार हैं। यूएस ओपन से पहले होने वाले प्रतिष्ठित सिनसिनाटी ओपन में दोनों को डबल्स ड्रॉ के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। टूर्नामेंट आयोजकों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह 2022 यूएस ओपन के बाद पहला अवसर होगा, जब दोनों बहनें किसी आधिकारिक मुकाबले में डबल्स जोड़ी के रूप में खेलती नजर आएंगी। वहीं, सिनसिनाटी ओपन में दोनों पहली बार एक साथ डबल्स खेलने उतरेंगी। इस साल विंबलडन में भी दोनों को डबल्स के लिए वाइल्ड कार्ड मिला था, लेकिन सेरेना विलियम्स की चोट के कारण यह जोड़ी कोर्ट पर नहीं उतर सकी थी।

**वापसी की राह पर सेरेना-** 44 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने हाल ही में लगभग चार साल बाद विंबलडन में सिंगल्स मुकाबले के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी की थी। हालांकि उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिनसिनाटी ओपन में वीनस के साथ डबल्स खेलना उनकी वापसी की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है।

**यूएस ओपन में भी दिखेंगी वीनस** 46 वर्षीय वीनस विलियम्स इस महीने के अंत में शुरू होने वाले यूएस ओपन में मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बब्लिक के साथ जोड़ी बनाकर खेलेंगी। यूएस ओपन से पहले सिनसिनाटी ओपन में विलियम्स बहनों की वापसी ने टेनिस प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। दोनों की जोड़ी एक बार फिर कोर्ट पर पुराने सुनहरे दिनों की यादें ताजा करने के इरादे से उतरेंगी।

**मनोरंजन** **बॉलीवुड का कोना**

# तोहफा ने बदली थी फैशन की तस्वीर, जया प्रदा ने सुनाया साड़ियों के दीवानों का दिलचस्प किस्सा

मुंबई। हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री जया प्रदा ने अपनी सुपरहिट फिल्म तोहफा के लोकप्रिय गीत प्यार का तोहफा से जुड़ी दिलचस्प यादें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि इस गीत ने केवल दर्शकों का दिल ही नहीं जीता था, बल्कि उनके द्वारा पहनी गई साड़ियों का ऐसा फैशन शुरू किया था कि बाजारों में उनकी भारी मांग हो गई थी। डांस आधारित कार्यक्रम इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचीं जया प्रदा और मीनाक्षी शेषाद्रि ने प्रतियोगी ऋतुराज और उनकी नृत्य साथी वैष्णवी की प्रस्तुति देखी। दोनों कलाकारों ने प्यार का तोहफा गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर जया प्रदा पुरानी यादों में खो गईं।

साड़ियों का ऐसा चला दौर कि दुकानों में होने लगी कमी

जया प्रदा ने बताया कि गीत के प्रदर्शित होने के बाद उनके नाम से साड़ियों का नया चलन शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि जब भी यह गीत सिनेमाघरों में बजता, लोग उनकी साड़ियों की चर्चा करते थे और बाजारों में वैसी ही साड़ियों की मांग अचानक बढ़ जाती थी। हालत यह हो गई थी कि कई दुकानों में वैसी साड़ियां मिलना मुश्किल हो जाता था।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां भी जाती थीं, लोग उन्हें देखकर तोहफा, तोहफा कहकर पुकारने लगते थे। उस समय उन्हें लगता था कि आखिर इतने सारे तोहफे वह कहां से लाएं। जया प्रदा ने कहा कि यह गीत उनके अभिनय जीवन की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक है।

### दक्षिण भारतीय निर्देशकों की रचनात्मक सोच की सराहना

मीनाक्षी शेषाद्रि ने कहा कि दक्षिण भारतीय फिल्मकारों, विशेषकर निर्देशक के. राघवेंद्र राव ने हिंदी सिनेमा को नई दृश्य शैली और भव्यता दी। उनके अनुसार प्यार का तोहफा में दिखाई गई साड़ियों और पूरे गीत की प्रस्तुति उस रचनात्मक सोच का शानदार उदाहरण थी, जिसने हिंदी फिल्मों को अलग पहचान दिलाई। साल 1984 में रिलीज हुई तोहफा का यह गीत उस दौर के सबसे लोकप्रिय गीतों में शामिल हुआ था। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज तथा बप्पी लाहिड़ी के संगीत ने इसे अमर बना दिया। गीत में जया प्रदा, श्रीदेवी और जितेंद्र की तिकड़ी ने अपने अभिनय और नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लिया था।

# प्रीति जिंटा ने मनाई हर दिल जो प्यार करेगा की 26वीं सालगिरह, बोलीं- आज भी यादें ताजा

मुंबई । अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्मों में काम किया, जो आज भी लोगों की पसंदीदा मूवीज लिस्ट में शामिल हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक है साल 2000 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, जिसमें प्रीति जिंटा ने जाह्नवी का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता था। अब फिल्म के 26 साल पूरे होने के मौके पर अभिनेत्री ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए एक खास पोस्ट साझा किया।

प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म को खास अंदाज में याद किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें फिल्म के कई यादगार सीन्स की छोटी-छोटी झलकियां दिखाई गईं। इस वीडियो में सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और शाहरुख खान नजर आए। वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म का टाइटल सॉन्ग हर दिल जो प्यार करेगा बज रहा था। प्रीति जिंटा ने इस वीडियो के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा। उन्होंने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को याद करते हुए लिखा, फिल्म को रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन यह अब भी हमारी पसंदीदा पुरानी यादों में शुमार है। फिल्म की 26वीं सालगिरह पर उन सभी दिलों को सेलिब्रेट करें, जो प्यार करना जानते हैं। बता दें कि फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन राज कंवर ने किया था, जबकि इसके निर्माता साजिद नाडियाडवाला थे। यह फिल्म सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला की सफल साझेदारी की लगातार तीसरी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही।

**मेट्रो बाजार**

# गोदरेज प्रॉपर्टीज का पहली तिमाही में मुनाफा 46% घटा

नई दिल्ली । देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी के मुनाफे और राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। जून तिमाही में कंपनी के समेकित शुद्ध लाभ (पीएटी) में तिमाही-दर-तिमाही 46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछली तिमाही के 650 करोड़ रुपए के मुकाबले 350 करोड़ रुपए रह गया। वहीं, पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले भी मुनाफा 41.7 प्रतिशत घटा है। एक साल पहले यह आंकड़ा 600 करोड़ रुपए था। कंपनी की ऑपरेशनल आय यानी परिचालन से राजस्व में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। जून तिमाही में राजस्व घटकर 506 करोड़ रुपए रह गया, जबकि मार्च तिमाही में यह 3,458 करोड़ रुपए था। इस तरह तिमाही आधार पर राजस्व में 85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, सालाना आधार पर कंपनी का राजस्व 16.5 प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 435 करोड़ रुपए था। परिचालन स्तर पर भी कंपनी का प्रदर्शन दबाव में रहा। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अप्रैल-जून तिमाही में 285 करोड़ रुपए का ईबीआईटीडीए घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ईबीआईटीडीए घाटा 243 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, कंपनी की अन्य आय भी घटकर 839 करोड़ रुपए रह गई, जो एक साल पहले 1,186 करोड़ रुपए थी। हालांकि, बिक्री और मांग के मोर्चे पर कंपनी को अच्छी सफलता मिली।

# एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा: 6.7 लाख से ज्यादा उद्यमों को मिला जेडईडी सर्टिफिकेशन

**नई दिल्ली** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन योजना के तहत अब तक करीब 9.49 लाख एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं। केंद्र सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को जेडईडी सर्टिफिकेशन पर 100 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत उद्यमों को गुणवत्ता-आधारित और पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाएं अपनाने में मदद देने के लिए अब तक 913 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। एमएसएमई मंत्रालय का कहना है कि जेडईडी योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बेहतर उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाने, गुणवत्ता मानकों में सुधार करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे भारतीय एमएसएमई घरेलू और वैश्विक बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत कर सकते हैं। जेडईडी पहल के तहत उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके जरिए

उद्यमों को तकनीक, सिस्टम और उत्पादन प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने में मदद मिलती है। योजना के तहत पंजीकृत उद्यमों में से 6.67 लाख एमएसएमई को ब्रॉन्ज, 6,700 को सिल्वर और 4,800 को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार, यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में छोटे उद्योग गुणवत्ता और पर्यावरणीय मानकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि जेडईडी योजना का प्रभाव केवल सर्टिफिकेशन तक ही सीमित नहीं है। देश के 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे अपनी औद्योगिक नीतियों का हिस्सा बनाया है।

# पूर्वोत्तर का अनमोल खजाना... ग्लॉव झील बनी भारत की 101वीं रामसर साइट

**ईटानगर।** अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत ग्लॉव झील को भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बन गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, जल सुरक्षा और सतत विकास को मजबूती देगी। पूर्वी हिमालय में स्थित ग्लॉव झील कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर मौजूद है और वाकरो से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है। झील और इसके आसपास के क्षेत्र में पेड़ों की 150 से अधिक तथा ऑर्किड की 49 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाथी, हिरण, विशाल गिलहरी और तेंदुआ बिल्ली जैसे वन्यजीव भी यहां निवास करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ ग्लॉव झील स्थानीय लोककथाओं और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। अक्टूबर से अप्रैल के बीच का समय यहां घूमने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।

## IPS बंसल को राष्ट्रपति भवन से सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों के चलते हटाया

**नई दिल्ली. एजेंसी**

राष्ट्रपति भवन में तैनात दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व संयुक्त पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) वीनू बंसल को उनके कथित असंसदीय व्यवहार और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद पद से हटा दिया गया है। सोमवार देर रात जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।

2004 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी वीनू बंसल राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त के विशेष कार्य अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त एस.के. जैन ने उनके तबादले का आदेश जारी किया। सूत्रों के मुताबिक, उनके व्यवहार से राष्ट्रपति भवन का स्टाफ नाराज था और कई कर्मचारी छुट्टी पर चले गए थे।

### छह छंद अनिवार्य करने के खिलाफ दायर पीआईएल पर अदालत की टिप्पणी

# मदरसों में वंदे मातरम् गाया जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा : हाईकोर्ट

**कोलकाता. एजेंसी**

मदरसों में 'वंदे मातरम्' के छह छंद गाना अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि यदि मदरसों में 'वंदे मातरम्' गाया जाएगा तो 'आसमान नहीं टूट पड़ेगा।'

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि देश में हजारों ईसाई स्कूल हैं, जहां सभी छात्र प्रार्थना में शामिल होते हैं। इससे किसी की धार्मिक पहचान खत्म नहीं होती। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में अधिकार क्षेत्र और कानूनी प्रक्रिया का पहलू महत्वपूर्ण है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि संविधान सभा में व्यापक चर्चा के बाद केवल दो छंदों को ही मान्यता दी गई थी। ऐसे में छह छंदों को अनिवार्य बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इसे गाना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अदालत ने पूछा कि क्या अब तक किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिसने 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार किया हो। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी ने अंतरिम रोक का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं केवल प्रचार हासिल करने का माध्यम बन रही हैं।

### हाई कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ी बहस

सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रगीत गाने से किसी की धार्मिक पहचान प्रभावित नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश के कई ईसाई स्कूलों में सभी छात्र प्रार्थना में शामिल होते हैं और इससे किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचता। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र से उसके धर्म से अलग कोई बात दोहराने को कहा जाता है, तो इससे वह अपने धर्म से बाहर नहीं हो जाता। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राष्ट्रगीत और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

### याचिकाकर्ताओं ने जताई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी कि संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद केवल 'वंदे मातरम्' के दो छंदों को मान्यता दी गई थी। ऐसे में छह छंदों को अनिवार्य बनाना संवैधानिक भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से राष्ट्रगीत गाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उनका दावा है कि इस फैसले से सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और समाज में अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है।

### संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन-नारेबाजी

# रिजिजू की राहुल और प्रियंका के साथ हुई बैठक, हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित

**नई दिल्ली. एजेंसी**

लोकसभा की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू हुई और एक मिनट में 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला।राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को जंतर-मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दें।संसद के मानसून सत्र में अब तक 8 में से 3 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। सरकार बाकी पांच बिलों को दोनों सदनों से पास कराने की तैयारी में है।

### भारतीय समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित

# अमेरिका में 28 हजार ट्रक ड्राइवरों पर गिरी गाज, अंग्रेजी नहीं आने पर लाइसेंस रद्द किया

**वॉशिंगटन. एजेंसी**

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अंग्रेजी भाषा के नियमों को सख्ती से लागू करते हुए 28 हजार से अधिक अप्रवासी ट्रक ड्राइवरों के कमर्शियल लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अब इनकी जगह सेना के पूर्व सैनिकों को ट्रक चालक के रूप में नियुक्त करने की योजना पर काम कर रही है।

अमेरिकी प्रशासन ने राज्यों के सहयोग से करीब 9,500 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। इन संस्थानों पर ऐसे अप्रवासी ड्राइवरों को लाइसेंस दिलाने में मदद करने का आरोप है, जिनकी अंग्रेजी भाषा पर पर्याप्त पकड़ नहीं थी। अगस्त 2025 में फ्लोरिडा में हुए एक भीषण सड़क हादसे के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। हादसे में एक ट्रक चालक के गलत यू-टर्न लेने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी परिवहन विभाग ने कमर्शियल ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका में करीब 1.3 से 1.5 लाख ट्रक चालक पंजाब और हरियाणा से जुड़े हैं। ऐसे में इस फैसले का सबसे अधिक असर भारतीय मूल के ड्राइवरों पर पड़ सकता है। परिवहन मंत्री शॉन डफी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो चालक अंग्रेजी नहीं समझते, उन्हें भारी वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

### भारतीय ट्रक ड्राइवरों की बढ़ी चिंता

अमेरिका के नए फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीय मूल के ट्रक चालकों पर पड़ने की आशंका है। आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में करीब 1.3 लाख से 1.5 लाख ट्रक चालक पंजाब और हरियाणा से जुड़े हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा अंग्रेजी भाषा के नियमों को सख्ती से लागू करने के बाद हजारों अप्रवासी चालकों के लाइसेंस रद किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी पढ़ना और समझना जरूरी है। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन ने सेना के पूर्व सैनिकों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विशेष छूट देने की घोषणा की है। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे, लेकिन अप्रवासी समुदाय के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है।

# इंदौर में मेडिकल विभाग के स्टोर कीपर पर EOW का छापा, करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा मामाला

**इंदौर. एजेंसी**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मेडिकल विभाग के स्टोर कीपर राकेश गोरखे के कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है।

जांच के दौरान राकेश गोरखे की कई जगहों पर संपत्तियां मिलने की जानकारी सामने आई है। इसमें वृंदावन गार्डन में तीन मंजिला मकान भी शामिल है। इसके अलावा संघवी रेसीडेंसी, सद्गुरु कॉलोनी बड़िया कीमा, साकार सिटी, साहिल रेसीडेंसी और ओमेक्स सिटी में भी प्रॉपर्टी मिलने की बात सामने आई है। जांच में सामने आया है कि राकेश गोरखे के पास उनकी ज्ञात आय की तुलना में करीब 110 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का आरोप है। इसी आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने उनके ठिकानों पर दबिश दी और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। फिलहाल जांच टीम सभी मकानों, प्लॉट, बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।

### झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले-

## 'यूपी-बिहार में आंदोलन करने पर इतने दिनों में मार दी जाती है गोली'

**रांची. एजेंसी।** झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएसएसी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं, छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जेपीएससी-जेएसएससी विरोध पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह दिल्ली वाला आंदोलन नहीं है। अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले से ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। यह दिल्ली नहीं है, यह दिल्ली वाला आंदोलन नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पेपर लीक का हब है, वहां हर 6 महीने में पेपर लीक होता है। फिर भी वहां कोई आवाज नहीं उठाता या सड़क पर नहीं उतरता, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी।

**मेट्रो एंकर** आईएएफ की 'मास्टरक्लास': पाक सीमा पर होगा महा-अभ्यास

# राफेल और सुखोई की ताकत देखने जोधपुर आ रहे आधा दर्जन देश

**जोधपुर. एजेंसी**

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की आधुनिक युद्ध क्षमता और सटीक रणनीति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर बिना किसी कोलेटरल डैमेज के की गई कार्रवाई के चलते कई मित्र देशों ने भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में रुचि दिखाई है। इसी कड़ी में अगले दो महीनों तक आईएएफ का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है।

फिलहाल भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'पिच ब्लैक' में हिस्सा ले रही है। इसमें भारत के चार राफेल, दो सी-17 ग्लोबमास्टर और 100 से अधिक वायुसैनिक शामिल हैं। इसके बाद अगस्त में मलेशिया के साथ 'उदारा शक्ति' और सितंबर में जापान के साथ 'वीर गार्जियन' अभ्यास आयोजित होगा। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर 12 से 23 सितंबर तक होने वाले 'वीर गार्जियन' में भारतीय सुखोई एसयू-30 एमकेआई और जापान के एफ-2 लड़ाकू विमान संयुक्त अभियान का अभ्यास करेंगे। इसके तुरंत बाद 26 सितंबर से शुरू होने वाला 'तरंग शक्ति 2026' भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा। पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने वाले इस अभ्यास में आधा दर्जन से अधिक देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लेंगे, जबकि कई अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। यह आयोजन भारतीय वायुसेना की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और सामरिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है।

### 'तरंग शक्ति 2026' में दिखेगी हमारी हवाई ताकत

राजस्थान का जोधपुर एयरबेस सितंबर में 'तरंग शक्ति 2026' की मेजबानी करेगा। यह भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसमें आधा दर्जन से अधिक देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ शामिल होंगे। कई अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। वर्ष 2024 में शुरू हुए 'तरंग शक्ति' के पहले संस्करण में राफेल, सुखोई, मिराज-2000, तेजस, मिग-29 और जैगुआर जैसे विमानों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। इस बार भी पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने वाले अभ्यास में आधुनिक हवाई युद्ध, एयर-टू-एयर रीफ्यूलिंग और विशेष सैन्य अभियानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत दुनिया के सामने दिखाई देगी।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 ( *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564